दैनिक

सिटी दर्पण

आईना सच का

चंडीगढ़ । मंगलवार, 2 जून, 2026 वर्ष 24, अंक 133, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

मान ने पंजाब में एचपीसीएल का बड़ा निवेश सुनिश्चित किया; रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे, मिलेगा रोजगार

रणनीतिक स्थिति, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण पंजाब उत्तरी भारत के पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में उभर रहा है : भगवंत सिंह मान

यज्ञांश शर्मा

चंडीगढ़

पंजाब के एक पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में उभार को उस समय बड़ा बढ़ावा मिला, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का बड़ा निवेश सुनिश्चित किया। इस ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने रिफाइनरी, बायोफ्यूल और बायोगैस क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से राज्य में अपना दायरा बढ़ाने की योजना का एलान किया है।

एचपीसीएल के चेयरमैन विकास कौशल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब के मजबूत बुनियादी ढांचे, रणनीतिक स्थिति, निवेशक-अनुकूल नीतियों और पारदर्शी शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला, जिसने राज्य को उत्तरी भारत के सबसे आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है। बैठक के दौरान एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने पंजाब में अपने कामकाज के और विस्तार का एलान भी किया, जिसमें बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से रोजगार पैदा होने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए टिकाऊ समाधान मिलने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उत्तरी भारत के पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में पंजाब की स्थिति को पेश किया। उन्होंने राज्य की भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और प्रमुख बंदरगाहों से निर्बाध संपर्क, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर, निर्बाध मानक बिजली आपूर्ति, कुशल कर्मचारियों और अग्रणी नीतियों के ताने-बाने के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने एचपीसीएल के प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के प्रशासनिक और नियामक सुधारों से भी अवगत कराया, जिसमें 173 से अधिक सरकारी-से-व्यापार (ऋ2इ) सेवाएं प्रदान करने वाला 'फास्ट ट्रैक पंजाब' सिंगल-विंडो सिस्टम, ऑटो-डीम्ड मंजूरी, पैन आधारित व्यापारिक पहचानकर्ता और 'पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट' में किए गए संशोधन शामिल हैं, जो समय पर साझा मंजूरी को संभव बनाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। हम नीतियों में स्थिरता, फैसले लेने में तेजी और ऐसी शासन प्रणाली प्रदान करके पंजाब को वैश्विक उद्योगों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाना चाहते हैं, जो निवेशकों के समय और भरोसे का सम्मान करे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यह बहुत उत्साहजनक है कि एचपीसीएल ने पंजाब में रिफाइनरी और बायोगैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ये निवेश राज्य को बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा देने के अलावा ये प्रोजेक्ट पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, यह खुशी की बात है कि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड 2जी तकनीक पर काम करके बठिंडा में अपने कामकाज का और विस्तार कर रही है। इस उपक्रम में कृषि अवशेषों से मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हुए बायोफ्यूल क्षेत्र को मजबूत करने की अपार संभावना है।

एचपीसीएल के प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विस्तार को सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, निवेशक सच्चे देशभक्त होते हैं, जो बड़े निवेश करके युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करके और अभूतपूर्व प्रगति तथा समृद्धि के युग की शुरूआत करके देश की सेवा करते हैं। पंजाब सरकार हर उस निवेशक के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, जो राज्य के विकास में योगदान देना चाहता है।

इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, उद्योग सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह, सचिव ग्रामीण विकास अजीत बालाजी जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

योग हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव स्वस्थ-संतुलित जीवन का आधार : नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान का किया शुभारंभ

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जिसने हजारों वर्षों से मानवता को संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। योग हमारे ऋषि-मुनियों और साधकों की अमूल्य देन है, जिसका वैश्विक स्तर पर सम्मान और अभिनंदन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क (लेजर वैली) में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में आयोजित राज्यव्यापी योग अभ्यास अभियान के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित योग साधकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा, नलवा के विधायक श्री रणबीर पनिहार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि योग किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि मानवता की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धरोहर है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला और 21 जून, 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तब से योग का वैश्विक विस्तार निरंतर बढ़ रहा है और करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत और योग की डोज, आधा घंटा रोज जैसे संदेश आज के समय की आवश्यकता हैं। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ, ऊजार्वान और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। 1 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में जिला, उपमंडल, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 21 जून को पंचकूला में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक जीवनशैली ने जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं तनाव, अनिद्रा, अनियमित खान-पान और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में योग शरीर को निरोगी, मन को स्थिर और जीवन को संतुलित बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की थीम योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा है। प्रदेश के युवाओं को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से योग को अपनाने और नशे से दूर रहने का आान भी किया।

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आान किया कि वे 21 जून तक आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा हरियाणा को देश का सबसे स्वस्थ, जागरूक और खुशहाल राज्य बनाने के संकल्प में सहभागी बनें। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने विभिन्न योग क्रियाओं के लाभ बताते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह तथा हजारो योग साधकों को सामूहिक योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मंडलायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता, सीपी शिवास कविराज, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, योग प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे।

बेटी पढ़कर आगे बढ़ेगी तो देश और समाज आगे बढ़ेगा: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी की विद्यार्थियों से अपील, सोशल मीडिया में न्यूनतम लगायें समय

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोजित समारोह में मेधावी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरिट में छात्राओं ने छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया है। यह सुखद संकेत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी पढ़कर आगे बढ़ेगी और देश व समाज आगे बढ़ेगा।

मेधावियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी सोशल मीडिया में न्यूनतम समय लगायें। सोशल मीडिया के ज्यादातर तथ्य झूठे होते हैं। समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। देश व समाज के बारे में जानकारी रखिए। अपनी परम्परा, संस्कृति व विरासत व अपने परिवेश के बारे में जानकारी रखें।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे यहां ज्ञान की समृद्ध परम्परा रही है। सा विद्या या विमुक्त्ये। जो हमारे जीवन में मुक्ति् का मार्ग प्रशस्त कर सके। चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा प्रदान कर सके। कभी भी भारत की परम्परा ने पलायन का रूख नहीं अपनाया। राम तब राम बने जब गुरू वशिष्ठ, मुनि विश्वामत्रि व महर्षि वाल्मीकि उनके जीवन में आये। कृष्ण तब कृष्ण बन पाये जब उनके जीवन में गुरू सांदीपनि आये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि सबसे बड़ी ज्ञान की धरोहर हमारे पास थी। इसीलिए भारत को विश्वगुरू कहा जाता है। पहले प्रदेश में नकलयुक्त परीक्षा होती थी। नौ वर्ष में हमने नकल विहीन परीक्षा कराने का काम प्रदेश में किया है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अनेक नवाचार किये गये हैं। आज समय पर परीक्षा होती है और समय पर परिणाम आते हैं। विद्यालय दर्शनीय हो गये हैं। राजकीय इण्टर कॉलेज हों या प्रबंधकीय व्यवस्था में सहायता प्राप्त विद्यालय हों या संस्कृत के विद्यालय इन सभी विद्यालयों के लिए अनुदान की व्यवस्था सरकार ने की है।

योगी ने कहा कि सार्टकट का मार्ग ठीक नहीं है। जीवन में परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारी सफलता के पीछे समाज व देश का भी योगदान है। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए।

इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी व लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहीं।

डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और दामाद बने जामनगर के मेहमान

एजेंसी (हि.स.)

जामनगर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल बोलोस विशेष विमान से गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर मोटीखावड़ी स्थित रिलायंस परिसर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

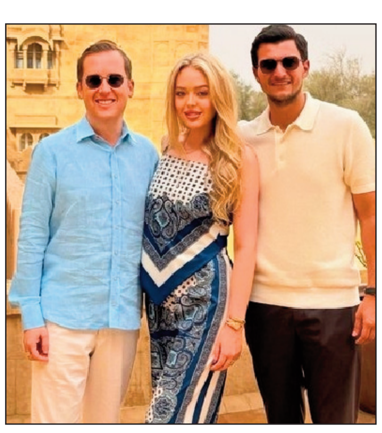

बताया जा रहा है कि वे विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव एवं पशु संरक्षण केंद्र ॠवनताराॠ का दौरा करने पहुंचे हैं। टिफनी ट्रंप और माइकल बोलोस की यात्रा को देखते हुए जामनगर पुलिस सहित विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। उनके काफिले में अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ वाहन, पायलट जीप और विशेष पुलिस एस्कॉर्ट वाहन शामिल थे। वीवीआईपी मूवमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एयरपोर्ट से मोटीखावड़ी तक पूरे मार्ग पर व्यापक बैरिकेडिंग की गई थी। काफिले के गुजरने के दौरान कुछ समय के लिए सामान्य यातायात भी रोका गया, जिसके चलते खंभालिया रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली।

टिफनी ट्रंप और माइकल बोलोस यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र ॠवनताराॠ का दौरा करेंगे। वे देश-विदेश की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के पशु-पक्षियों को देखेंगे तथा वन्यजीव संरक्षण, पुनर्वास और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी वैश्विक स्तर की व्यवस्थाओं की जानकारी विशेषज्ञों से प्राप्त करेंगे।

इस बीच टिफनी ट्रंप ने अपने आधिकारिक एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत यात्रा के कई फोटो और वीडियो भी साझा किए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और अतिथि सत्कार की खुलकर सराहना की है।

राहुल गांधी पुष्कर पहुंचे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में करेंगे संवाद

एजेंसी (हि.स.)

अजमेर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार सुबह अजमेर के निकट तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। वे किशनगढ़ हवाई अड्डे से सड़क मार्ग के जरिए पुष्कर स्थित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जहां राजस्थान और दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधायक विकास चौधरी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। प्रशिक्षण स्थल पर गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल सहित अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनका दौरा निरस्त हो गया।

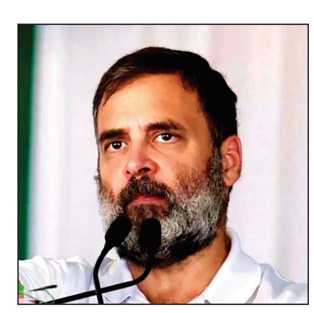

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान और दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे संगठनात्मक विषयों, आगामी चुनावों की तैयारियों, जनसंपर्क, डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्रबंधन तथा जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के मुद्दों पर संवाद करेंगे। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों के परिवारजनों से भी मुलाकात करेंगे। पुष्कर स्थित वाइल्ड रोज रिसॉर्ट में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले राजस्थान और दिल्ली प्रदेश के 65 जिलाध्यक्षों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी ने परिवारजनों से मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तथा कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई वरिष्ठ नेता पूर्व में भी प्रशिक्षण शिविर में भाग ले चुके हैं।

मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश बनेगा समृद्ध : शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी (हि.स.)

भोपाल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी ह्यखेत बचाओ अभियानह्न का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संदेश दिया कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने देशभर में 01 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी सेहत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ज्यादा रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन और खेती की लागत पर पड़ता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ह्यखेत बचाओ अभियानह्न केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारी, कृषि विभाग की टीमें और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, आधुनिक बुवाई तकनीक, जल संरक्षण और उन्नत खेती के तरीके सिखाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हर किसान का सॉयल हेल्थ कार्ड बनना जरूरी है, ताकि किसान अपनी जमीन की जरूरत समझकर खाद का उपयोग करे। इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका मतलब जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं है। सही मात्रा में खाद का उपयोग ही टिकाऊ खेती की कुंजी है।

उन्होंने कहा कि खेती को लाभकारी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, धान और दलहन फसलों के लिए क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक बुवाई, लेजर लेवलर जैसी आधुनिक तकनीक और पानी बचाने वाली खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि रमासिया गांव से शुरू हुआ यह अभियान आगे चलकर जनभागीदारी का बड़ा आंदोलन बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से गांवों में पहुंचें, किसानों को तकनीकी सहायता दें और खेती को बचाने के इस संकल्प को जमीन पर उतारें। उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे विकास अभियानों में सक्रिय भागीदारी करें, क्योंकि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही समृद्ध गांव, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण संभव है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत विजनरी हैं, बहुत पहले बहुत दूर का सोचते हैं। ये धरती माता केवल हमारे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो इसकी हालत ऐसी ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इंकार कर दे, इसलिए माटी बची रहे, इसलिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, धरती के तत्वों की आवश्यकता देखते हुए करने की बात करेंगे। केवल इतना ही नहीं, नकली पेस्टीसाइड और खाद उसके खिलाफ भी अभियान चलेगा।

कार्यक्रम में विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा और राकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। इसी प्रकार प्रधान वैज्ञानिक डॉ आरके सिंह ने प्राकृतिक खेती, डॉ एमपी सिंह ने खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती और डॉ यूसी दुबे खरीफ फसलों हेतु कृषि यंत्रीकरण एवं कृषि मशीनरी के बारे में किसानों को जानकारी दी।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी में कृषि एवं उद्यानिकी सहित अन्य विभागों और प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया और जानकारी ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अनेक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। साथ ही किसानों को उड़द और सोयाबीन बीज किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने कम वजन वाले बच्चों को फूड बॉस्केट भी वितरित किए।

इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता हित वरिष्ठ कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

हज यात्रियों के सामान की सुरक्षित और तत्काल डिलीवरी के लिए मांगा हस्तक्षेप

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सऊदी अरब से पवित्र हज यात्रा संपन्न कर लौट रहे केंद्र शासित प्रदेश के हाजियों के सामान के परिवहन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को एक अर्धशासकीय पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन संबंधी दिक्कतों और रनवे के चल रहे रखरखाव कार्य के कारण यात्रियों को हो रही भारी असुविधाओं का हवाला देते हुए इस संवेदनशील मामले में तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक तकनीकी कारणों के चलते तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं और उनके परिवारों की सामाजिक परंपराओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पत्र में श्रीनगर हवाई अड्डे पर लागू परिचालन संबंधी प्रतिबंधों और भार सीमाओं (लोड पेनल्टी) का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि हालिया व्यवस्था के तहत सऊदी अरब से लौट रहे हज यात्रियों का चेक-इन किया हुआ भारी सामान उन उड़ानों में साथ नहीं लाया जा रहा है जिनमें यात्री खुद सफर कर रहे हैं। इसके बजाय, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं कि यात्रियों के सामान को अन्य उड़ानों के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है और वहां से उसे सड़क मार्ग के जरिए जम्मू-

कश्मीर भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि लंबी दूरी के कारण सड़क मार्ग से सामान की डिलीवरी होने में कई दिनों का लंबा समय लग सकता है, जिससे न केवल सामान के सुरक्षित रहने पर संशय पैदा हो रहा है बल्कि बुजुर्ग यात्रियों को भी बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों और हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन दिनों रनवे के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक तकनीकी रख-रखाव का कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य की वजह से उड़ानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के कुल भार को लेकर सख्त नियम (लोड रिस्ट्रिक्शन्स) लागू किए गए हैं। इसी भार प्रतिबंध के चलते हज यात्रियों के भारी सामान, जिसमें पवित्र आब-ए-जमजम (पवित्र जल) की केन और बड़े बैग शामिल हैं, को यात्रियों की मुख्य उड़ानों में लोड करना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पा रहा है।

इसी कारण एयरलाइंस और प्रशासनिक एजेंसियों ने सामान को वैकल्पिक रूप से अहमदाबाद रूट से सड़क मार्ग द्वारा श्रीनगर भेजने की विशेष सामान व्यवस्था तैयार की है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सऊदी अरब से लौटने वाले अधिकांश हाजी बुजुर्ग हैं। इनमें से कई लोगों ने जीवन भर की अपनी जमापूंजी लगाकर और वर्षों की लंबी प्रतीक्षा व भक्ति के बाद इस अत्यंत पवित्र धार्मिक यात्रा की आकांक्षा को पूरा किया है। ऐसे में आगमन के समय हवाई अड्डे पर अपने ही सामान की डिलीवरी के लिए उन्हें दिनों-दिनों तक इंतजार करवाना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर चल रहे कार्यों का सम्मान करते हुए भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित न होना पड़े और उनका सामान सुरक्षित तरीके से उन तक समय पर पहुंच सके।

जनगणना 2027: हिमाचल में स्व-गणना अभियान शुरू, राज्यपाल ने खुद भरकर किया आगाज

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्व-गणना अभियान की शुरूआत हो गई है। राज्यपाल ने सोमवार को लोकभवन से इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। राज्य में यह अभियान 1 जून से 15 जून 2026 तक चलाया जाएगा। अभियान की शुरूआत करते हुए राज्यपाल ने स्वयं अपनी स्व-गणना पूरी की और प्रदेशवासियों से भी इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश की निदेशक और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने राज्यपाल को स्व-गणना की डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी दी। स्व-गणना पूरी करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की संख्या गिनने का काम नहीं है, बल्कि यह भविष्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की नींव तैयार करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्रीय कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और 1 जून से 15 जून के बीच स्वेच्छा से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करे। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे स्व-गणना के दौरान सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार लोगों से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार और लागू कर सकती हैं। इससे जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्व-गणना पूरी होने के बाद पोर्टल से एक स्व-गणना आईडीजारी होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके बाद 16 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच जब प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे, तब नागरिकों को यह आईडी उन्हें उपलब्ध करानी होगी, जिससे जनगणना का काम आसानी से पूरा हो सके। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद कई महत्वपूर्ण आंकड़े अपडेट नहीं हो पाए हैं। नई जनगणना से न केवल ताजा और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, बल्कि विकास योजनाओं को भी बेहतर दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे अधिकतर बर्फबारी वाले राज्यों में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस डिजिटल पहल को सफल बनाने और समय पर अपनी स्व-गणना पूरी कर राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

हिमाचल में 3 दिन आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, जून में ठंडा मौसम

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जून को प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

लगातार हो रही बारिश और बादल छाए रहने से प्रदेश में गर्मी का असर काफी कम हो गया है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली समेत पहाड़ी क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह में ही मौसम ठंडा बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में भी सामान्य तौर पर पड़ने वाली जून की तपिश महसूस नहीं हो रही है। सोमवार को भी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई, जबकि कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। ओले गिरने से सेब और अन्य गुठलीदार फलों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 3 जून से 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 3 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के कुछ क्षेत्रों में आंधी, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

मौजूदा चुनाव नतीजे 2027 की तस्वीर नहीं, राजनीति में तेजी से बदलते हैं हालातः रोहित ठाकुर

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषद चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन चुनाव परिणामों को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कम समय के भीतर भी समीकरण बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर रहेगा। रोहित ठाकुर ने सोमवार को कहा कि जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जनसमर्थन मिला है। उनके अनुसार जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की चारों जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बताया कि जुब्बल विकास खंड की सभी 15 बीडीसी सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं, जबकि कोटखाई विकास खंड की 15 में से 11 बीडीसी सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसके अलावा पंचायत प्रधान और उपप्रधान पदों पर भी लगभग 75 से 80 प्रतिशत कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है।

नगर निगम चुनाव में हार की करेंगे समीक्षा संगठन को और मजबूत बनाएंगे : विक्रमादित्य सिंह

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत और जिला परिषद चुनावों में भाजपा की बढ़त के बाद कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर शुरू हो गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनावों में मिली हार के कारणों की समीक्षा करेगी और संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की नई संगठनात्मक टीम के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी नेताओं और कार्यकताओं को साथ लेकर चलेगी तथा संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने माना कि तीन नगर

निगमों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसके पीछे के कारणों पर पार्टी स्तर पर विस्तार से चर्चा और आत्ममंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई स्थानों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उनके अनुसार पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की अपनी अलग प्रकृति होती है, जहां उम्मीदवार का व्यक्तिगत व्यवहार, स्थानीय रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रधान और स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन चुनावों का स्थानीय स्तर पर विशेष महत्व होता है। भाजपा की ओर से इस समय जो बड़े-बड़े राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं और सरकार की स्थिरता को लेकर जो कहानियां बनाई जा रही हैं, उनकी वास्तविक स्थिति आने वाले समय में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। जनता सब जानती है। हमारी सरकार पूरी तरह मजबूत है और हम चुनावी नतीजों की समीक्षा कर विकास के एजेंडे पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान जिलों के प्रभारी मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक कर सकता है, जिसमें उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां भितरघात या कमजोर प्रबंधन के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल, हिमाचल की राजनीति में इस हार-जीत के बाद दोनों ही दल आगामी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं।

संक्षिप्त-समाचार

तम्बाकू सेवन से तीन गुना बढ़ता है टीबी का खतरा कांगड़ा में 20 प्रतिशत मरीज तंबाकू सेवन वाले

धर्मशाला। तम्बाकू सेवन करने वाले लोगों में टीबी होने का खतरा सामान्य व्यक्तियों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक होता है। यही नहीं, तम्बाकू टीबी के उपचार की सफलता को भी प्रभावित करता है और जटिलताओं व मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह जानकारी रविवार को धर्मशाला में आयोजित टीबी सेवाओं और तम्बाकू निषेध सेवाओं के बेहतर समन्वय संबंधी कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला का आयोजन टीबी रोगियों को तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रभावी सहायता उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के कर्मचारियों और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. विवेक करोल ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिले में पंजीकृत 977 टीबी रोगियों में से 200 रोगी तम्बाकू का सेवन करते हैं, जो कुल मरीजों का लगभग 20 प्रतिशत है। इनमें से 163 रोगियों को तम्बाकू निषेध हेल्पलाइन से जोड़ा जा चुका है, जहां उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए विशेषज्ञ परामर्श और सहायता प्रदान की जा रही है।

बारामूला पुलिस ने खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की, दो टिप्पर जब्त

बारामूला। अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने खनिजों के अवैध परिवहन में शामिल होने के लिए पंजीकरण संख्या जेके 05 बी-1271 और जेके05 ए-4592 वाले दो टिप्परों को रोका और जब्त कर लिया। वाहन खनिज निष्कर्षण और परिवहन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। तदनुसार उल्लंघनकताओं के खिलाफ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। बारामूला पुलिस अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का गैरकानूनी दोहन भी होता है। ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस का सहयोग करें और अपने-अपने क्षेत्रों में खनिजों के अवैध खनन या परिवहन के संबंध में जानकारी साझा करें।

अनंतनाग पुलिस ने जिले भर में सोमवार की परेड का किया आयोजन

अनंतनाग। अनंतनाग पुलिस ने आज जिले के सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में साप्ताहिक सोमवार की परेड का आयोजन किया जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के अनुशासन, वेशभूषा और परिचालन तत्परता का आकलन करना था। मुख्य कार्यक्रम जिला पुलिस लाइन्स (डीपीएल) अनंतनाग में आयोजित किया गया जहां एएसपी नॉर्थ कैंप ऐशमुकाम रमीज राजा ने परेड का निरीक्षण किया और मार्चिंग टुकड़ियों से सलामी ली। परेड में विभिन्न पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। परेड के बाद अधिकारी ने डीपीएल अनंतनाग में विभिन्न प्रतिष्ठानों और सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की, बुनियादी ढांचे के रखरखाव का आकलन किया और अनुशासन, स्वच्छता और तत्परता के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि साप्ताहिक सोमवार की परेड व्यावसायिकता को मजबूत करने, परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने और बल की समग्र तत्परता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।

बीके शिवानी तीन जून को मंडी संबंधों में समरसता पर देंगी व्याख्यान

मंडी। विश्वविख्यात आध्यात्मिक मार्गप्रदर्शक परामर्शदाता एवं प्रेरक वक्ता बीके शिवानी आगामी तीन जून को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में अपना प्रबोधन देंगी। प्रजापिता ब्रम्हाकुमारीज संस्था की ओर से आयोजित की जा रही आध्यात्मिक संध्या में मंडी जिला के विभिन्न अंचलों से हजारों की तादाद में लोग बीके शिवानी की भावपूर्ण वाणी का श्रवण करने के लिए मौजूद रहेंगे। ब्रम्हाकुमारीज संस्था मंडी सेंटर की संचालक बीके शीला दीदी ने बताया कि तीन जून को सांय साढ़े पांच से साढ़े सात बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम से पूर्व पांच बजे से साढ़े पांच बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए बीके शीला दीदी ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रवेश निशुल्क किया गया। जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मंडी शहर के अलावा, जोगिंद्रनगर, करसोग, बालीचौकी, पंडोह, सुंदरनगर, पधर, चुराग, भंगरोटू, तल्यायहड़, बगस्याड, रिवालसर, सरकाघाट, कोटली, चैलचौक और सलापड़ आदि स्थानों से हजारों लोग कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देंगे। उन्होंने बताया कि ऑन लाइन पास दो जून को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक और शाम चार से आठ बजे तक पास लिए जा सकते हैं। उनहोंने बताया कि इस कार्यक्रम में बारह साल से अधिक आयु वर्ग के लोग भग ले सकेंगे। वहीं पर अपने साथ पानी की बोतल अवश्य लेते आएं और नो प्लास्टिक की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि प्रजापिता ब्रम्हाकुमारीज विश्वविद्यालय में आत्मा की उन्नति की शिक्षा दी जाती है। इस समय दुनिया अशांति के दौर से गुजर रही है। वास्तव में सभी एक आत्मा है, हम शरीर को भेजन दे रहे हैं। लेकिन आतमा को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। जिसकी वजह से आत्मा अशांत रहती है। आने वाले समय में मंडी में तीन दिन का राजयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिससे हमारे जीवन व संस्कारों में परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि परेशानी के कारण ही बच्चे नशे की ओर मुड़ रहे हैं।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा को मिला जनसमर्थन कांग्रेस सरकार पर साधा निशानाः राजेंद्र राणा

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर द्वारा सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रकार वार्ता की शुरूआत करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पंचायत समिति, जिला परिषद और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिला व्यापक जनसमर्थन प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यशैली के प्रति जनता की नाराजगी को दशार्ता है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा की सफलता जनता के स्पष्ट जनादेश का संकेत है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार लंबे समय तक स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों को लेकर असमंजस में रही तथा विभिन्न कारणों का हवाला देकर चुनाव टालने का प्रयास किया गया।

उन्होंने कहा कि अब चुनाव परिणामों ने सरकार के प्रति जनता की वास्तविक भावना को उजागर कर दिया है। राणा ने दावा किया कि हमीरपुर जिला परिषद की 19 सीटों में कांग्रेस को केवल एक सीट पर सफलता मिली, जबकि अधिकांश सीटों पर उसे निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के प्रति घटते जनविश्वास का संकेत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भाजपा को प्राप्त समर्थन के आधार पर पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी अपना नेतृत्व स्थापित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिससे कर्मचारियों, महिलाओं और अन्य वर्गों में असंतोष बढ़ा है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेताओं के संबंध में राणा ने कहा कि ऐसे मामलों को अनुशासन समिति के पास भेज दिया गया है और अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।

नशा-विरोधी अभियान जम्मू-कश्मीर में एक जन आंदोलन में बदल गया है : उपराज्यपाल

कुलगाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को भावनात्मक और जन-केंद्रित रूप से बढ़ावा दिया और खुद को आपके परिवार का सदस्य बताते हुए जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की लत और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में प्रशासन के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लारू बस स्टैंड पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 51 दिन पहले शुरू किया गया नशा-विरोधी अभियान जम्मू-कश्मीर में एक जन आंदोलन में बदल गया है जिसमें परिवारों, युवाओं, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज समूहों की सक्रिय भागीदारी है। सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके संघर्ष और एक सुरक्षित, संरक्षित और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर के आपके सपने का समर्थन करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान अब सरकारी विभागों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को शामिल करते हुए एक सामूहिक सामाजिक मिशन में परिवर्तित हो गया है।

सुक्खू सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता ने कर ली तैयारी : राकेश शर्मा

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम, पंचायतों व जिला परिषद चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता सुक्खू सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार बैठी हुई है। इन चुनावों में जनता ने सुक्खू सरकार की खिंचाई की तो उसे जमीन भी नजर आ गई है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के कुशासन, जनविरोधी नीतियों और खराब कामकाज को पूरी तरह नकार दिया है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और नीतियों के साथ मजबूती से खड़ी है जनता ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार सालों से झूठ की बुनियाद पर बैठी सुक्खू सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में कई वर्ष पीछे घकेल दिया है। इन चुनावों के परिणामों से साफ जाहिर हुआ है कि प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार से दुखी व परेशान है तथा कांग्रेस सरकार से जनता जल्द छुटकारा चाहती है। सोमवार को जारी एक प्रेस बयान में राकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद लोगों को विकास की उम्मीद थी, लेकिन जनता को निराशा हाथ लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक अव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के नतीजे बताते हैं कि लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठ चुका है। जनता अब बदलाव चाहती है और यही वजह है कि शहरी इलाकों में भाजपा को मजबूत समर्थन मिला है।

कठुआ में शहीद अमरनाथ भगत को भावभीनी श्रद्धांजलि

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

कठुआ में शहीद अमरनाथ भगत की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधायक डॉ. भारत भूषण सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकत्र होकर महान समाज सुधारक और शहीद को नमन किया।

सभा में उपस्थित लोगों ने शहीद अमरनाथ भगत के उस ऐतिहासिक योगदान को याद किया जिसके माध्यम से उन्होंने जम्मू-कश्मीर में वंचित और कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन समाज के लिए समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण रहा। शहीद अमरनाथ भगत का जन्म वर्ष 1928 में जिला रामबन के चम्पा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे समाज सेवा के प्रति समर्पित थे और उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। आजादी के बाद देश के अन्य हिस्सों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा था लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह व्यवस्था वर्ष 1970 तक लागू नहीं हुई थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अमरनाथ भगत ने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं के साथ मिलकर 1970 में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। जब सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने 21 मई 1970 को आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और अंततः 1 जून 1970 को उन्होंने समाज के हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

परिणाम पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ हुआ कांग्रेस विरोधी माहौल: भाजपा

पंचायती चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ : अनुराग ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनावों के परिणामों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से आए परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जिला परिषद चुनावों में 19 सीटों में से कांग्रेस केवल एक सीट जीत पाई, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की और शेष सीटों पर भी कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनकी पार्टी का इतना कमजोर प्रदर्शन जनता की नाराजगी का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति (बीडीसी) चुनावों के परिणाम भी कांग्रेस सरकार

> हमीरपुर जिले की कुल 119 पंचायत समिति सीटों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 80 सीटों पर विजय हासिल की जबकि कांग्रेस केवल 32 सीटों तक सिमट गई

की विफलताओं की कहानी स्वयं बयां कर रहे हैं। हमीरपुर जिले की कुल 119 पंचायत समिति सीटों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 80 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 32 सीटों तक सिमट गई। सात सीटों पर निर्दलीय अथवा न्यूट्रल उम्मीदवार विजयी रहे। उन्होंने कहा कि लगभग दो-तिहाई सीटों पर भाजपा की जीत यह दशार्ती है कि जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने

सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराशा ही हाथ लगी है। कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम जनता से किए गए वादे अधूरे पड़े हैं। यही कारण है कि स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए भाजपा के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कांग्रेस सरकार जनभावनाओं से कट चुकी है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस का न केवल हमीरपुर जिले में बल्कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जनाधार तेजी से सिमट रहा है। यह परिणाम केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली के प्रति जनता की नाराजगी का प्रतिबिंब हैं।

अनुराग ठाकुर ने भाजपा समर्थित सभी विजयी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने हमीरपुर जिला तथा प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है।

सड़क सुधार कार्यों में समन्वय से कार्य करें सभी विभाग : नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करना है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के साथ संवाद बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक एवं जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बन सके।

मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 03 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान गुरुग्राम की सड़क व्यवस्था और आधारभूत ढांचे से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एचएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम गुरुग्राम तथा जीएमडीए के अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति पर जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को केवल प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर स्वयं भी उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां सड़क मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक सड़क सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार की म्हारी सड़क ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी सड़क संबंधी समस्या का शीघ्र निवारण हो सके और आमजन को बेहतर एवं सुरक्षित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में लक्ष्मण विहार निवासी एक महिला शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि एक फाइनेंसर ने ऋण के लेनदेन के दौरान विश्वास का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी से उनके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह बकाया राशि लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंसर मकान पर कब्जा बनाए हुए है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान तैनात रहे संबंधित तहसीलदार की भूमिका की भी जांच कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने फाइनेंसर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने तथा मकान को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सेक्टर-4 निवासी एक शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर-4 में मौजूद सभी प्रमुख समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन को भी निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को बंद करने से पूर्व शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। शिकायतकर्ता की सहमति और संतुष्टि प्राप्त होने के बाद ही शिकायत के निस्तारण को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि आमजन को वास्तविक राहत मिल सके और शिकायत निवारण प्रणाली पर उनका विश्वास और मजबूत हो।

इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुपवा में आज खुलेगा पीजी एडमिशन का पोर्टल

सिटी दर्पण संवाददाता

रोहतक

10 जुलाई तक जमा कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए एडमिशन पोर्टल आज खुलेगा। जिसमें ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स, मास्टर ऑफ डिजाइन व मास्टर ऑफ प्लानिंग में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। छात्रों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर 10 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना होगा। डीन अकेडमिक अफेयर्स डॉ अजय कौशिक ने बताया कि 2 जून को पीजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। 10 जुलाई तक छात्र पंजीकरण शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जमा करा सकेंगे। 17 जुलाई को नोटिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइनल परिणाम घोषित किया जाएगा। 14 जुलाई को पहली काउंसिलिंग होगी व प्रवेश शुल्क जमा कराया जाएगा। 3 अगस्त को नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत होगी। उन्होंने बताया कि छात्र विजुअल आर्ट्स फैकेल्टी में मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स में दाखिला ले सकते हैं। यहां अप्लाइड आर्ट्स, पेंटिंग, प्रिंटमेकिंग, स्कल्पचर में पीजी की जा सकती है। जबकि डिजाइन फैकेल्टी में मास्टर ऑफ डिजाइन में छात्र दाखिला ले सकेंगे। इसके तहत फैशन डिजाइन व टेक्सटाइल डिजाइन में पीजी की जा सकती है। इसके अलावा प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर फैकेल्टी में मास्टर ऑफ प्लानिंग (अर्बन एवं रिजनल) में प्रवेश लिया जा सकता है। डॉ कौशिक ने बताया कि सुपवा में यूजी कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया पहले से चल रही है। 15 मई को यूजी कोर्सेज में प्रवेश का ऑनलाइन पोर्टल ओपन हुआ था।

हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के हित में लिया एक और निर्णय

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

एकमुश्त निपटान योजना-2026 का बढ़ाया समय

हरियाणा सरकार ने व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के व्यापारियों के लंबे समय से लंबित पड़े टैक्स मामलों के स्थाई और त्वरित निपटान के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर एकमुश्त निपटान योजना-2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के व्यापारिक समुदाय को अदालती मुकदमों और पुराने टैक्स विवादों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकेगी, जिससे प्रदेश में व्यापार करने की सुगमता को और बढ़ावा मिलेगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना के क्रियान्वयन और समय-सीमा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष राहत योजना आज यानी 1 जून 2026 से शुरू होकर आगामी 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रूप से लागू रहेगी। उन्होंने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि हरियाणा सरकार की यह नीति पहले भी व्यापारियों के बीच बेहद लोकप्रिय और सफल रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ष 2025 में भी प्रदेश के रिकॉर्ड 1,15,223 व्यापारियों ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया था और अपने पुराने कर विवादों को सुलझाया था।

छोटे और बड़े करदाताओं को मिलने वाली वित्तीय राहत को लेकर सरकार ने इस बार और भी ज्यादा उदार और सरल प्रावधान किए हैं। इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि जिन छोटे करदाताओं पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये तक का टैक्स बकाया है, उनका कर, ब्याज और जुमार्ना बिना किसी आवेदन के स्वतः (ऑटोमेटिकली) माफ कर दिया जाएगा, यानी उन्हें किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत जिन व्यापारियों का बकाया 1 लाख रुपये से अधिक का है, उनके मामलों में सरकार द्वारा 70 प्रतिशत तक टैक्स छूट का एक बेहतरीन प्रावधान किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि व्यापारियों को आर्थिक संबल देने के लिए इसमें और भी कई बड़ी सहूलियतें जोड़ी गई हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र मामलों में व्यापारियों को ब्याज और जुमार्ने में पूरे 100 फीसदी की भारी छूट दी जाएगी, जिससे उनकी वर्षों पुरानी बड़ी देनदारियां बेहद कम हो जाएंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने व्यापारियों की नकदी की समस्या और व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह भी बड़ी राहत दी है कि वे अपनी अंतिम निपटान राशि का भुगतान एक साथ करने के बजाय आसान किस्तों में भी कर सकेंगे।

सरकार का यह निर्णय किसी एक सीमित क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद व्यापक रखा गया है। इस पूरी योजना के तहत हरियाणा सरकार के कुल 7 टैक्स अधिनियमों के तहत आने वाले तमाम लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा सरकार अपने राज्य के व्यापारियों को देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ मानती है, और प्रवक्ता के अनुसार यह एकमुश्त निपटान योजना-2026 राज्य के व्यापारी भाई-बहनों को पुराने करों के मानसिक और आर्थिक बोझ से मुक्त कर उन्हें निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

सरकार ने सभी पात्र व्यापारियों से अपील की है कि वे समय रहते 28 सितंबर से पहले इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

प्रदेश में तीन नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी मिली : आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आमजन तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत गुरुग्राम, भिवानी और हिसार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय आबादी को सीधे तौर पर आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

सरकार के इस निर्णय के अनुसार गुरुग्राम जिला के गांव घामडोज में एक नया उप-स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, जबकि भिवानी जिला के गांव धनाना तथा हिसार जिला के गांव सिसाय बोला में एक-एक नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों के बनने से आसपास के दर्जनों गांवों की निर्भरता बड़े शहरों के अस्पतालों पर कम होगी।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज या आपातकालीन स्थिति में दूरदराज के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि उन्हें उनके घर के नजदीक ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे जोड़ा कि इन नए सामुदायिक और उप-स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से स्थानीय स्तर पर मुफ्त दवाएं, जांच और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

सरकार का लक्ष्य आगामी दिनों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना है ताकि 'स्वस्थ हरियाणा' के संकल्प को धरातल पर उतारा जा सके।

भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था, वह पूरी तरह छलावा साबित हुआ है। आज स्थिति यह है कि खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में एनपीके और पोटाश जैसे उर्वरकों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। एनपीके (12:32:16), एनपीके (16:16:16), पोटाश तथा अन्य मिश्रित उर्वरकों के दामों में प्रति बैग सैकड़ों रुपये की वृद्धि हुई है। इससे खेती की लागत में हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ किसानों पर पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने में विफल रही है, वहीं दूसरी ओर खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को लगातार महंगा किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी देने के बजाय सरकार बड़े उद्योगपतियों और निजी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इसका सीधा असर देश के अन्नदाताओं पर पड़ रहा है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सहित पूरे देश का किसान आज बढ़ती लागत, कम आय और कर्ज के दबाव से परेशान है। भाजपा सरकार के दस वर्षों में किसानों की समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ी हैं। किसानों को राहत देने के लिए खाद एवं कृषि आदानों की कीमतों पर नियंत्रण, डीजल पर राहत और फसलों के लिए लाभकारी एमएसपी सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है और भविष्य में भी किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है और उसकी समृद्धि के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि वापस ली जाए तथा किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।

संक्षिप्त-समाचार

शहीद मदन लाल ढींगडा स्मारक समिति के निर्विरोध प्रधान बने विधायक अशोक अरोड़ा

कुरुक्षेत्र। पंजाबी धर्मशाला के अर्जुन सभागार में शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक समिति की कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी राजन चावला एडवोकेट ने जानकारी दी कि आगामी 3 वर्षों के लिए कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध हुआ। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इससे पूर्व पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निर्धारित तिथि 20 मई तक पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए नामांकन भरे गए थे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में जहां श्री अशोक अरोड़ा को प्रधान चुना गया वहीं महासचिव के पद पर दीनानाथ अरोड़ा एडवोकेट को निर्वाचित किया। सभी चुनाव सर्वसम्मति से हुए। वरिष्ठ उपप्रधान ओम प्रकाश गुलियानी और नरेंद्र ढींगरा, उप प्रधान गुलशन गाबा तथा विवेक मेहता विक्की, सचिव सोमप्रकाश सचदेवा, कोषाध्यक्ष राजेश पोपली को निर्वाचित घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के 11 सदस्यों के पद पर पवन मिगलानी, संजय कौशल, रामस्वरूप चोपड़ा, कुलवंत राय छाबड़ा एडवोकेट, कृष्ण धमीजा, गर्व बटला, बलदेव राज एडवोकेट, राकेश ढल सीए, अश्विनी अरोड़ा एडवोकेट, सतीश ललित, राजकुमार ढींगड़ा को निर्वाचित घोषित किया गया। इसी के साथ साथ डॉ एसी नागपाल, विजय सभरवाल, अविनाशी लाल अरोड़ा तथा मक्खन लाल रल्हन को समिति का संरक्षक बनाया गया। नव निर्वाचित प्रधान अशोक अरोड़ा ने सर्व सम्मति से चुनाव संपन्न होने पर सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से समिति के कार्यों को आगे बढाया जाएगा। पंजाबी धर्मशाला के वेंकट हाल को शीघ्र ही वातानुकूलित किया जाएगा। बैठक में समिति के सैंकड़ों सदस्यों ने भाग लिया तथा सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होने पर प्रधान श्री अशोक अरोड़ा तथा अन्य पदाधिकारियों का फूल माला डालकर स्वागत किया। सभा के नवनिर्वाचित महासचिव दीनानाथ अरोड़ा एडवोकेट ने सभी सदस्यों का आभार जताया।

साइलेंस ऑफ मोमेंट्स मौन अनुभवों की सशक्त अभिव्यक्ति: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रख्यात छायाकार डॉ. पवन कुमार की एकल छायाचित्र प्रदर्शनी ह्यसाइलेंस ऑफ मोमेंट्सह्व का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में प्रकृति, समय, स्मृति और जीवन के अनकहे एवं मौन क्षणों को कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शकों को गहन संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करती है। उद्घाटन अवसर पर कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि समाज और परिवेश को अधिक संवेदनशीलता एवं गहराई से समझने की दृष्टि भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि ह्यसाइलेंस ऑफ मोमेंट्सह्व समय, स्मृति और अनुभव के उन मौन आयामों को उजागर करती है, जो मनुष्य और उसके परिवेश के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि कला मनुष्य की संवेदनाओं को समृद्ध करने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक सोच का विकास भी करती है। ललित कला विभाग के अध्यक्ष डॉ. गुरचरण सिंह ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों और युवा कलाकारों के लिए सीखने, समझने और अपनी रचनात्मक दृष्टि को विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर होती हैं। उन्होंने कहा कि कला केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संवेदनशील अवलोकन, धैर्य और निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थी कला के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को निकटता से समझ सकेंगे। छायाकार डॉ. पवन कुमार ने कहा कि यह प्रदर्शनी शोधार्थियों और विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की बारीकियों, दृश्य संरचना, प्रकाश, छाया तथा क्षण की संवेदनात्मक शक्ति को समझने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर अधिष्ठाता प्रो. कृष्णा रंगा, प्रो. एस. के. चहल, लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया, कुटा प्रधान डॉ. जितेंद्र खटकड़,कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डॉ. यदुवीर सिंह,डॉ सौरभ चौधरी डॉ. विनोद कुमार, विभाग के अध्यक्ष, डॉ. गुरचरण सिंह, छायाकार डॉ. पवन कुमार, डॉ. मोनिका गुप्ता, डॉ. आनंद जायसवाल, डॉ. राकेश बानी, डॉ. आर. के. सिंह, सुशील रंगा, शोधार्थी, और छात्र भी उपस्थित थे।

फसल मुआवजा राशि जारी करने पर किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार

कुरुक्षेत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीका ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 के फसल खराबे पर दो बार में किसानों के खाते में 486.67 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया जा चुका है। इनमें 8 मई 2026 को 370.52 करोड़ और 10 दिसंबर 2025 में 116.16 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मुआवजा राशि में से गुहला तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों को 3 करोड़ 87 लाख 56 हजार 590 रुपए मिले हैं। इसी तरह पिहोवा तहसील के अंतर्गत आने वाले किसानों के खाते में 5 करोड़ 41 लाख 2 हजार 638 रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के खातों में फसल मुआवजा राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेर्शों पर प्रशासन द्वारा गिरदावरी के बाद मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। समय पर मिली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और उन्हें अगली फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में मुआवजा वितरण प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और त्वरित हो गई है।

इग्नू में जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रारम्भ

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

इग्नू में लगभग 350 तरह के पाठ्यक्रम: डॉ धर्म पाल

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू देश का सबसे बड़ा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है, जो गुणवत्तापूर्ण, लचीली एवं किफायती शिक्षा के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए इग्नू में अनेक आकर्षक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीएजी), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम), बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए), बैचलर ऑफ सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू), बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (बीलिस) तथा विभिन्न विषयों में ऑनर्स डिग्री कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधन, शिक्षा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, कंप्यूटर, पर्यावरण, योग, संस्कृत, उर्दू, उद्यमिता, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे क्षेत्रों में भी अनेक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू लगभग 350 से अधिक प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों, नौकरीपेशा व्यक्तियों, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, दिव्यांगजनों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 312 ईआरवी वाहनों को दिखाई हरी झंडी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिलें और 2 होंडा एलिवेट गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ-साथ आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नई ईआरवी के माध्यम से पुलिस की पहुंच बढ़ेगी और संकट की स्थिति में लोगों को पहले से अधिक तेजी से सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित पुलिस व्यवस्था ही नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करती है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश में पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटाकर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता को समय पर सहायता उपलब्ध कराना ही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिलें और एक होंडा एलिवेट गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और एक होंडा एलिवेट गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिलें दी गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी भी सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से जनहित के कार्यों को नई गति मिलती है और यह पहल भी उसी सोच का उदाहरण है।

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि नई ईआरवी के शामिल होने से हरियाणा पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये वाहन किसी भी सूचना पर तेजी से घटनास्थल तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जिससे लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना और अधिक आसान होगा।

पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित ये वाहन पुलिसिंग को और प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल आधारित ईआरवी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संकरी गलियों में तेजी से पहुंचकर आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा नागरिकों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने में सहायक साबित होंगी।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला देवी, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, एचएमएसआई के सीनियर डायरेक्टर एवं होंडा इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी विनय ढींगरा, एचएमएसआई की डायरेक्टर सचिमी ताकाता, एचएमएसआई के डायरेक्टर एवं सीएफओ तोयोहिरो हाबा तथा होंडा इंडिया फाउंडेशन के ऑपरेटिंग ऑफिसर राजीव तनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: उम्मीद की नई किरण

दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर सभी प्रमुख बिंदु तय हो चुके हैं और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह घोषणा न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि इससे भारतीय उद्योग जगत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के नेताओं ने 3 फरवरी 2026 को ही एक रूपरेखा समझौते की घोषणा की थी। अब उस रूपरेखा को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गोर ने भी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि समझौते की 99 प्रतिशत बातें तय हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत की एक टीम बीती सप्ताह वाशिंगटन डीसी गई थी ताकि शेष एक प्रतिशत विवरण को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके साथ ही, इस सप्ताह 2, 3 और 4 जून को नई दिल्ली में भी वार्ता के दौर आयोजित किए जाएंगे। इस समझौते की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 18 प्रतिशत का समान शुल्क लागू किया था। इससे वस्त्र, चमड़ा, जूते-चप्पल, गृह सज्जा और हस्तशिल्प उद्योग जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हुए। ऐसे में यह व्यापार समझौता न केवल इन शुल्कों को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने में भी सहायक होगा। पिछले दो दशकों में भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। यह आँकड़ा स्वयं इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंध कितनी तेजी से गहरे हुए हैं। अब जब पहले चरण के समझौते पर सहमति बनती दिख रही है, तो यह साझेदारी और अधिक संस्थागत एवं दीर्घकालिक स्वरूप ग्रहण करेगी। हालाँकि, यह समझना भी जरूरी है कि यह पहला चरण एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में महज पहली सीढ़ी है। गोयल ने स्वयं कहा कि पहले चरण के हस्ताक्षर के बाद अधिक व्यापक और समावेशी समझौते की ओर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसका अर्थ है कि सेवा क्षेत्र, डिजिटल व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और निवेश जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत चर्चा अभी शेष है। इस समझौते से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण कानूनी जटिलता भी है। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लगाए गए कई शुल्कों को असंवैधानिक करार दे दिया। इसका प्रभाव यह होगा कि भारत के साथ होने वाले समझौते में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कानूनी संरचना के अनुरूप बदलावों को शामिल करना होगा। गोयल ने स्पष्ट किया कि यह समझौता अमेरिका की शुल्क व्यवस्था में हो रहे कानूनी परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करेगा, जो समझौते को दीर्घकालिक रूप से स्थिर और टिकाऊ बनाएगा। भारत के लिए यह क्षण रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ पुनर्गठित हो रही हैं और अनेक देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों की होड़ में हैं, तब भारत का यह कदम उसे एक पसंदीदा और विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में स्थापित करता है। यदि यह समझौता समयसीमा के भीतर संपन्न होता है, तो यह न केवल दोनों देशों के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक साख को भी नई ऊँचाई देगा। संक्षेप में, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में यह प्रगति स्वागतयोग्य है। अब आवश्यकता इस बात की है कि शेष वार्ताएँ पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से पूरी की जाएँ, ताकि भारत इस ऐतिहासिक अवसर का पूरा लाभ उठा सके।

संरा. की चिंता और चरागाह भूमि का संकट

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 2026 को चरागाह और पशुचारक वर्ष घोषित किया है। इससे जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर चरागाह भूमि संकट ग्रस्त हैं और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। इनका क्षेत्रफल भूमि उपयोग में बदलाव के कारण घटता जा रहा है। अतिदोहन और खरपतवारों के कारण इनकी उपजाऊ क्षमता लगातार घटती जा रही है। दुनिया में चरागाह, सवाना घास के मैदान, झाड़ीदार जंगल, रेगिस्तान, पर्वतीय चरागाह, खुले वन और कृषि वानिकी क्षेत्र इसी श्रेणी में शामिल हैं। वैश्विक क्षेत्रफल का 54% भू-भाग किसी न किसी प्रकार की चरागाह भूमि में शामिल है, जिसमें से 78% शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। एक तिहाई जैव विविधता इन्ही क्षेत्रों पर निर्भर है। विश्व खाद्य उत्पादन का 16% इन्हीं क्षेत्रों से आता है। चरागाह क्षेत्र भूमि को पोषक तत्व प्रदान करने के अतिरिक्त कार्बन प्रचूषण, इको टूरिज्म,और मनोरंजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल चरागाह क्षेत्र का 50% भाग अनुत्पादक होने के कगार पर है।

देश में चरागाह भूमि का क्षेत्रफल 1210 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 1000 लाख हेक्टेयर अच्छी स्थिति में नहीं है और पूर्ण उपयोगिता के स्तर की भूमिका निभाने में असमर्थ है। इसके चलते पशु चारक समुदाय हाशिये पर आते जा रहे हैं और सरकारी नीतियों में भी उनके हितों की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खनन और ऊर्जा परियोजनाएं इन क्षेत्रों में पहुंच को सीमित करती जा रही हैं। देश में ढाई करोड़ लोग पूर्णतः पशुपालन पर आजीविका के लिए निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे भू-मालिकों की दो तिहाई आबादी को पशुपालन से 16% आजीविका का आधार प्राप्त होता है। भारत में कुल पशु संख्या 53 करोड़ 61 लाख के लगभग है, जिसमें से गाय, भैंस, मिथुन, याक 30 करोड़ 31 लाख हैं। बाकी सूअर, घोडा, भेड़, बकरी आदि हैं। चरागाह भूमि के भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि कटाव आदि से नुकसान के अलावा खरपतवार आक्रमण से भी चरागाह भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। खरपतवार चरागाहों की उत्पादकता को 90% तक नष्ट कर देते हैं। लेंटाना, युपिटोरियम, पार्थेनियम, एजरेटम आदि प्रमुख खरपतवार हैं जो चरागाहों को भारी हानि पंहुचा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लें तो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 55 लाख 67 हजार हेक्टेयर में से 15 लाख 11 हजार हेक्टेयर चरागाह भूमि है, जिसमें से 6000 फुट की ऊंचाई से कम वाले क्षेत्रों की चरागाह लगभग 80% खरपतवारों की चपेट में आ कर अनुत्पादक हो चुकी है। प्रदेश में 2020 की पशु गणना के मुताबिक 44 लाख 13 हजार पशु धन है। जो 2012 की गणना के मुकाबले काफी कम है, जिसका मुख्य कारण पशु चारे की कमी है। भारतीय घास-चारा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रदेश में हरे चारे की आपूर्ति में 20.30% और सूखे चारे की उपलब्धता में 53.61% की कमी है। इस कमी की पूर्ति करने के लिए पशुपालक पंजाब और हरियाणा से गेहूं और धान का भूसा आयात करते हैं जो 10 से 15 रुपये किलो तक यहां पहुंचता है। इतने महंगे चारे से पशु पालन घाटे का सौदा हो गया है। इसी कारण लोग पशु पालन से मुंह मोड़ रहे हैं। पशु सडकों में छोड़े जारहे हैं।

इससे फसलें तबाह हो रही हैं और दुर्घटनाओं को न्योता मिल रहा है। हालांकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पशु पालन का 28.8% योगदान है किन्तु पशुपालन को पेश मुख्य समस्याओं की ओर सम्यक ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन मुख्यतः चराई पर निर्भर था। यदि चरागाह में पर्याप्त घास हो तो पशु पालन में लगने वाले श्रम और लागत में आधी कटौती हो जाती है। खूंटे पर बांध कर पशुपालन वह भी आयातित चारे के आधार पर करना काफी महंगा मामला है। हालांकि पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने दूध के मूल्य में बढ़ोतरी करने आदि कुछ कदम उठाए हैं किन्तु मुख्य समस्या तो चारे की है। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दुर्भाग्य से सारी चरागाह भूमि भी प्रबंधन के लिए वन विभाग के अधीन है। चरागाह प्रबंधन वन विभाग की मान्य कार्ययोजना का हिस्सा ही नहीं है। इनकी भाषा में तो चरागाहों को प्रति भूमि कहा जाता है, जबकि चरागाह वेस्ट लैंड नहीं हैं, उत्पादक प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि उनमें घास उत्पादन की क्षमता घट जाती है तो उन्हें कम उपजाऊ चरागाह कहा जा सकता है न कि वेस्ट लैंड। जब इस विषय पर सरकार को लिखा तो उन्होंने यह मामला पशुपालन विभाग को भेज दिया। पशुपालन विभाग के पास तो चरगाह भूमि का नियंत्रण ही नहीं है न ही उनके पास चरागाह सुधार के लिए कोई बजट ही है। इस तरह चरागाह भूमि ऐसी भूमि बन कर रह गई हैं जिनका कोई वारिस नहीं है। वन विभाग तो पहले ही इन भूमि पर चीड़ रोपण करके घास उत्पादन को समाप्त करने का काम कर चुका है। उनके वर्किंग प्लान में अभी भी चरागाह विकास का तो कोई वर्किंग सर्कल ही नहीं है।

केवल कुछ परियोजनाओं के माध्यम से सिल्वी पेस्टोरल मॉडल खड़े करने के प्रयास हुए हैं किन्तु वह मांग और क्षेत्र की दृष्टि से नाकाफी हैं। उनका अभी तक कोई प्रत्यक्ष सफल मॉडल देखने को कम ही सामने आया है। हालांकि कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर और भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान पालमपुर के पास खरपतवार उन्मूलन करके चरागाह को उपजाऊ बनाने का पर्याप्त अनुभव और तकनीक और घासों के बीज उपलब्ध है, किन्तु जरूरत है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में उपयुक्त ध्यान देकर चरागाह विकास को प्रदेश के लिए 28.8% सकल घरेलू उत्पाद का योगदान देने वाले पशुपालन कार्य को तदनुरुप प्राथमिकता देकर बजट प्रावधान और प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करे। विश्व चरागाह और पशुचारक वर्ष में इस दिशा में की गई पहल एक सकारात्मक वैश्विक संदेश भी साबित होगी।

(लेखक, पर्यावरणविद और हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष हैं।)

भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोले

1 जून से लागू हो रहा भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस मिशन की एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य नए बाजार खोलने और रोजगार सृजन को गति देने के जरिये भारत के छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के लिए वैश्विक समृद्धि के मार्ग बनाना है।

भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200झ300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह तुरंत ही ओमान में 98% टैरिफ लाइनों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की सुविधा देता है, जिसमें 99.38 प्रतिशत निर्यात शामिल है।

यह सीईपीए से पहले की प्रणाली की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत भारतीय निर्यात ओमान में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते थे। भारत की ऐसी वस्तुएं, जिन पर वर्तमान में ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जिनकी कीमत लगभग 3.64 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर है, अब काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए, यह समझौता परिवर्तनकारी हो सकता है, क्योंकि सीईपीए से लाभान्वित होने वाले कई क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की प्रमुखता है। लोहा और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, वाहन कल-पुर्जे और औद्योगिक उपकरण जैसे कुछ क्षेत्रों में एमएसएमई को बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के युग में, सीईपीए भारतीय निर्यातकों को, जो आर्थिक मंदी और बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, अपने बाजारों को विविध बनाने और परंपरागत बाजारों पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

पीयूष गोयल

रोजगार सृजन झ यह व्यापार समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्रों को लाभ पहुँचाता है, जो भारत के प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं। ओमान को होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, भदोही, मुरादाबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख क्लस्टर में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। भारत भर के कारीगर और बुनकर भी अपने उत्पादों की उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होंगे।

भारत भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछहिस्सों समेत चमड़ा और जूता के प्रमुख केंद्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रत्न और आभूषण क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है, जो दिखाता है कि सीईपीए रोजगार वृद्धि को किस प्रकार तेज करेगा। भारत के पास पहले से ही कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण तथा हस्तनिर्मित आभूषण उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। शुल्क बाधाओं के हटने से, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में ओमान को होने वाला निर्यात बढ़ कर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आभूषण निर्माण केन्द्रों में महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है।

किसान और मछुआरे - घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि हितों की सुरक्षा के लिए, भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, तिलहन, चाय, कॉफी और शहद जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरीफ छूट नहीं दी है।

घी, शहद, मीठे बिस्कुट, अंडे और कुछ मिष्ठान्न उत्पादों में भारत को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे देश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। यह समझौता भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणन की स्वीकृति और मान्यता भी प्रदान करता है, जो भारतीय किसानों को ओमान में, जो एक प्रमुख खाद्य आयातक है, जैविक उत्पाद बेचने के लिए विशाल अवसर देगा।

समुद्री उत्पादों में भी विशाल संभावनाएँ हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। 2022 और 2024 के बीच ओमान का समुद्री उत्पादों का आयात लगभग 119 मिलियन डॉलर था। भारत से आयात केवल 7.75 मिलियन डॉलर था, जिससे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात जैसे झींगा और जमे हुए कटलफिश के लिए विशाल अवसर मौजूद हैं। श्रम-गहन समुद्री उत्पाद उद्योग मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत-श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और निर्यात संचालन में अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न कर सकता है।

दवा और पारंपरिक चिकित्सा - यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए और टीजीए जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित भारतीय दवाएं 90 दिनों के भीतर ओमान में स्वचालित विपणन प्राधिकार प्राप्त करेंगी – जो भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए एक बड़ी सफलता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि सीईपीए भारत की पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। यह पारंपरिक चिकित्सा में संयुक्त अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

सेवाएँ और आवागमन - समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा और आवागमन में निहित है। ओमान ने भारत के लिए विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, कंप्यूटर और आईटी सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरण सेवाएँ शामिल हैं। लेखा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, निर्माण, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुँच से लाभ मिलने की उम्मीद है।

महत्त्वपूर्ण रूप से, ओमान ने भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के लिए आवागमन प्रतिबद्धताओं में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है। अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों और संविदा सेवा प्रदाताओं को चार साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि व्यवसाय आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों को आसान अस्थायी प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इसने अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों के लिए ऊपरी-सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की मोदी सरकार की पहल प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा है।

ओमान के साथ समझौता याद दिलाता है कि व्यापार; विकास, रोजगार सृजन और साझा समृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक विभाजित और संरक्षणवादी दुनिया में, पीएम मोदी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि एक नया, आत्मविश्वासी भारत पीछे नहीं हटेगा। यह साझेदारियों, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ेगा।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज आपका मन नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करने और विभिन्न विषयों को समझने में लगेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। दिनचर्या व्यवस्थित और अनुशासित रहने से कार्यों में सफलता मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों को परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। कीमती वस्तुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। मन में किसी बात को लेकर असंतोष बना रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी। वरिष्ठ एवं प्रभावशाली लोगों के बीच आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में भागीदारी मिल सकती है। परिवार में अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आज नए लोगों से परिचय होने और मित्रता बढ़ने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर कुछ सहकर्मियों के व्यवहार से मन आहत हो सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। प्रेम जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आपका सामाजिक दायरा विस्तृत होगा और नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। रिश्तों में केवल औपचारिकता निभाने की बजाय भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास करें। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा। पुराने वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: व्यापार और करियर से जुड़े मामलों में आपको गहन सोच-विचार के साथ निर्णय लेने होंगे। कारोबार में कुछ असहज परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं। रिश्तेदारों और परिचितों के साथ सौम्य व्यवहार बनाए रखें। कार्यालय में कभी-कभी अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

धनु: व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। महिलाएँ सौंदर्य और साज-सज्जा से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च कर सकती हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। विवाह योग्य लोगों के लिए नए रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आपके मन में कुछ नया और रचनात्मक करने की इच्छा जागृत होगी। कार्यस्थल पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। जब तक किसी व्यक्ति पर पूरा विश्वास न हो, तब तक निजी बातें साझा करने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर आप काफी सजग रहेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मीन: नया वाहन खरीदने या किसी बड़ी खरीदारी की योजना बन सकती है। परिवार के साथ सुखद और यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा। व्यापारिक समस्याओं के समाधान से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई तकनीक और आधुनिक तरीकों का उपयोग लाभदायक सिद्ध होगा। *(सिटी दर्पण)*

सोशल मीडिया ट्रेंड और एल्गोरिदम की भूमिका

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनमत होता है। यह जनमत किसी एक दिन या एक चुनाव के दौरान निर्मित नहीं होता, बल्कि समाज में निरंतर चलने वाले संवाद, बहस, विचार-विमर्श, सामाजिक अनुभवों, राजनीतिक चेतना और नागरिक भागीदारी की लंबी प्रक्रिया से आकार लेता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का सूचित निर्णय, विभिन्न विचारों का आदान-प्रदान और असहमति के प्रति सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लंबे समय तक देश में जनमत के निर्माण का आधार प्रत्यक्ष संवाद, जनसभाएं, सामाजिक संगठन, समाचार-पत्र, पुस्तकें, शिक्षण संस्थान और जन आंदोलन रहे। लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद यह परिदृश्य तेजी से बदला है। आज सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह जनमत निर्माण की सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। ऐसे समय में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अब जनमत नागरिकों के स्वतंत्र चिंतन से अधिक सोशल मीडिया ट्रेंड और एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित होने लगा है?

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ता समूहों में से एक भी। करोड़ों लोग प्रतिदिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यू-ट्यूब, व्हाट्स ऐप और अन्य डिजिटल मंचों का उपयोग करते हैं। समाचारों से लेकर राजनीतिक विचारों तक, समाज के बड़े वर्ग की प्राथमिक जानकारी अब इन्हीं प्लेटफॉर्मों से प्राप्त होती है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले जहां नागरिक किसी मुद्दे पर अखबार पढ़कर, बहस सुनकर या स्थानीय स्तर पर चर्चा करके राय बनाते थे, वहीं अब राय निर्माण की प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल मंचों पर निर्भर हो गई है। इस प्रक्रिया में सोशल मीडिया एल्गोरिदम की भूमिका केंद्रीय हो गई है।

एल्गोरिदम ऐसे तकनीकी तंत्र हैं जो यह तय करते हैं कि किसी उपयोगकर्ता को कौन-सी सामग्री दिखाई जाएगी और कौन-सी नहीं। वे उपयोगकर्ता की पसंद, गतिविधियों, खोज इतिहास और ऑनलाइन व्यवहार का विश्लेषण करके सामग्री का चयन करते हैं। तकनीकी दृष्टि से उनका उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है, क्योंकि डिजिटल कंपनियों का आर्थिक मॉडल इसी पर आधारित है। लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टि से यह प्रक्रिया कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि नागरिकों को वही सामग्री दिखाई जाए जो उनकी पूर्व मान्यताओं से मेल खाती हो, तो क्या वे विविध विचारों से परिचित हो पाएंगे? यदि एल्गोरिदम यह तय करने लगें कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो क्या लोकतांत्रिक विमर्श स्वतंत्र रह पाएगा?

आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना किसी विषय की लोकप्रियता का प्रमुख संकेतक माना जाता है। कोई हैशटैग लाखों बार साझा हो जाए तो वह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो ट्रेंड कर रहा है वही जनभावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि ट्रेंड वास्तव में समाज की व्यापक राय का प्रतिबिंब हो। अनेक बार ट्रेंड संगठित डिजिटल अभियानों, राजनीतिक प्रचार, भुगतान आधारित प्रचार रणनीतियों या बॉट नेटवर्क द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल दृश्यता और वास्तविक जनसमर्थन हमेशा समानार्थी नहीं होते।

जमीनी स्तर की राजनीतिक भागीदारी और डिजिटल सक्रियता के बीच का अंतर भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास प्रत्यक्ष जन सहभागिता के अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने जेल यात्राएं कीं, सत्याग्रह किए और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाए। बाद के दशकों में भी अनेक आंदोलनों ने नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से संगठित किया। इन आंदोलनों में लोगों के बीच संवाद, विश्वास और सामूहिकता का निर्माण होता था। इसके विपरीत डिजिटल सक्रियता अकसर प्रतीकात्मक भागीदारी तक सीमित रह जाती है। किसी पोस्ट को साझा करना, किसी हैशटैग का समर्थन करना या प्रोफाइल फोटो बदलना आसान है, लेकिन यह हमेशा वास्तविक सामाजिक हस्तक्षेप में परिवर्तित नहीं होता। परिणामस्वरूप राजनीतिक भागीदारी का एक नया स्वरूप विकसित हुआ है जिसमें दृश्यता अधिक और प्रत्यक्ष सामाजिक प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है।

सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव तथाकथित 'इको चैंबर' और 'फिल्टर बबल' के रूप में सामने आता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की सामग्री देखता या पसंद करता है, तो एल्गोरिदम उसे उसी प्रकार की और सामग्री दिखाने लगते हैं। धीरे-धीरे वह व्यक्ति ऐसे डिजिटल वातावरण में पहुंच जाता है जहां उसे मुख्यतः वही विचार दिखाई देते हैं जिनसे वह पहले से सहमत होता है। इससे वैचारिक विविधता कम हो जाती है और विरोधी विचारों के प्रति असहिष्णुता बढ़ने लगती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए तैयार हों। लेकिन यदि एल्गोरिदम नागरिकों को वैचारिक रूप से अलग-अलग खेमों में बांट दें, तो लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है।

भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक समूह अपने-अपने डिजिटल समुदायों में सक्रिय रहते हैं। इन समुदायों के भीतर साझा की जाने वाली सामग्री अक्सर एक विशेष दृष्टिकोण को पुष्ट करती है और विरोधी विचारों को संदेह, उपहास या शत्रुता की दृष्टि से प्रस्तुत करती है। इससे समाज में संवाद की जगह टकराव की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक और आवश्यक है, लेकिन जब असहमति संवाद के बजाय वैमनस्य का रूप लेने लगे तो लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है।

फेक न्यूज और दुष्प्रचार का प्रश्न भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम से गहराई से जुड़ा हुआ है। एल्गोरिदम उन सामग्रियों को अधिक बढ़ावा देते हैं जिन पर लोग तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर भावनात्मक और सनसनीखेज सामग्री तथ्यात्मक और संतुलित सामग्री की तुलना में अधिक तेजी से फैलती है। यही कारण है कि झूठी खबरें, आधे-अधूरे तथ्य, भ्रामक वीडियो और मनगढ़ंत दावे सोशल मीडिया पर अत्यंत तेजी से वायरल हो जाते हैं। भारत में कई अवसरों पर फेक न्यूज ने सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक विवाद और सार्वजनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की है। चुनावी राजनीति में भी गलत सूचनाओं का उपयोग मतदाताओं की राय को प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। जब नागरिकों के निर्णय तथ्यात्मक जानकारी के बजाय दुष्प्रचार पर आधारित होने लगें, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

सोशल मीडिया ने राजनीतिक संचार को भी पूरी तरह बदल दिया है। पहले राजनीतिक दलों को जनता तक पहुंचने के लिए रैलियों, सभाओं, पोस्टरों और पारंपरिक मीडिया का सहारा लेना पड़ता था। अब वे सीधे नागरिकों के मोबाइल फोन तक पहुंच सकते हैं। यह सुविधा लोकतंत्र के लिए सकारात्मक भी है क्योंकि इससे सूचना का प्रवाह तेज हुआ है। लेकिन इसके साथ ही माइक्रो-टार्गेटिंग जैसी नई रणनीतियां भी विकसित हुई हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के व्यवहार से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करते हैं। इस डेटा के आधार पर अलग-अलग समूहों को अलग-अलग राजनीतिक संदेश भेजे जा सकते हैं। इससे राजनीतिक प्रचार अधिक प्रभावी तो हो जाता है, लेकिन पारदर्शिता कम हो जाती है। नागरिकों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें जो संदेश दिखाया जा रहा है, वही संदेश अन्य नागरिकों को भी दिखाई दे रहा है या नहीं। लोकतंत्र का आदर्श सार्वजनिक और खुला विमर्श है, जबकि माइक्रो-टार्गेटिंग राजनीतिक संवाद को खंडित और निजी बना सकती है।

हालांकि सोशल मीडिया और एल्गोरिदम के प्रभाव को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। इन मंचों ने अनेक सकारात्मक अवसर भी प्रदान किए हैं। समाज के हाशिए पर स्थित समूहों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण समुदायों और अल्पप्रतिनिधित्व वाले वर्गों को अपनी बात रखने का नया मंच मिला है। कई सामाजिक मुद्दे जो पहले मुख्यधारा मीडिया में पर्याप्त स्थान नहीं पाते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय बहस का विषय बने हैं। डिजिटल माध्यमों ने सूचना तक पहुंच को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है और नागरिकों को सत्ता से सीधे संवाद करने का अवसर दिया है। कई जनहित अभियानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक समर्थन प्राप्त किया है। प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक आंदोलनों और जनजागरुकता अभियानों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की सकारात्मक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब तकनीकी मंच स्वयं लोकतांत्रिक विमर्श के निर्णायक बनने लगते हैं। किसी लोकतंत्र में यह निर्णय नागरिकों और संस्थाओं का होना चाहिए कि कौन-से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, न कि किसी निजी कंपनी के एल्गोरिदम का। लेकिन व्यवहार में कई बार यही होता दिखाई देता है कि जो विषय एल्गोरिदमिक रूप से अधिक दृश्यता प्राप्त कर लेता है, वही सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ जाता है। इससे उन महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है जो डिजिटल रूप से आकर्षक नहीं हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण संकट, श्रमिक अधिकार, शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन जैसे विषय अक्सर मनोरंजक या विवादास्पद सामग्री की भीड़ में दब जाते हैं। हमारे लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह डिजिटल तकनीक के लाभों को स्वीकार करते हुए उसके दुष्प्रभावों को कैसे नियंत्रित करे। इसके लिए केवल सरकारी नियमन पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि नागरिक सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मीडिया साक्षरता तथा तथ्य-जांच संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपने एल्गोरिदम की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। राजनीतिक विज्ञापनों और डिजिटल प्रचार अभियानों के लिए स्पष्ट नियमों की आवश्यकता है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता बनी रहे। स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

जब ट्रेंड जनमत को प्रभावित करने लगें, तब नागरिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें यह समझना होगा कि हर वायरल सामग्री सत्य नहीं होती, हर ट्रेंड जनभावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता और हर डिजिटल बहस लोकतांत्रिक विमर्श नहीं होती। लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाएं नहीं करतीं, बल्कि सचेत नागरिक भी करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल युग में नागरिक तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित न हों। यदि हम ऐसा कर पाए, तो सोशल मीडिया लोकतंत्र को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगा, अन्यथा यह खतरा बना रहेगा कि एक दिन जनमत नागरिकों की स्वतंत्र चेतना से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम द्वारा निर्मित ट्रेंड से निर्धारित होने लगेगा। यही हमारे समय की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

बड़ी इन्फोर्समेंट सफलताओं के कारण पंजाब ने मई 2026 के दौरान 14.59% जी.एस.टी. बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा : हरपाल सिंह चीमा

कुल जी.एस.टी. प्राप्ति में 305 करोड़ रुपये से अधिक की शानदार बढ़ोतरी: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की मजबूत वित्तीय कार्यक्षमता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने मई 2026 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्राप्ति में 14.59 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है।

वित्त मंत्री चीमा ने बताया, इस महीने की कुल जी.एस.टी. कलेक्शन 2,400.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो मई 2025 के दौरान प्राप्त 2,094.81 करोड़ रुपये की तुलना में 305.71 करोड़ रुपये की बड़ी बढ़ोतरी दर्शाती है।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह शानदार बढ़ोतरी निरंतर आर्थिक गतिविधियों, बेहतर टैक्स अनुपालन और आबकारी एवं कर विभाग द्वारा इन्फोर्समेंट उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का नतीजा है।

एक प्रेस बयान में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब की जी.एस.टी. कार्यक्षमता राष्ट्रीय रुझानों की तुलना में बेहद शानदार रही है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में देश के कुल जी.एस.टी. राजस्व के लगभग 3.2 प्रतिशत बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है।

उन्होंने कहा, जहां पंजाब की नकद उगाही (कैश कलेक्शन) में वृद्धि 6.57 प्रतिशत रही, वहीं राज्य की कुल जी.एस.टी. बढ़ोतरी 14.59 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो राज्य के राजस्व आधार के मजबूत होने, टैक्स अनुपालन के स्तर में सुधार और बेहद प्रभावी टैक्स प्रशासन के उपायों को दर्शाता है।

इन्फोर्समेंट उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, पूरे पंजाब में स्टेट इंटेलीजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (सिपू) ने केवल मई 2026 के दौरान 182.69 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाकर और 178.76 करोड़ रुपये की वसूली करके शानदार परिणाम दिए हैं।

उन्होंने बताया कि यह बड़ी वसूली व्यापक डेटा विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स), गुप्त जानकारी आधारित जांचों, निश्चित वेरिफिकेशन अभियानों और राज्य भर में समन्वय के साथ चलाए गए फील्ड ऑपरेशनों के कारण संभव हुई है।

टैक्स चोरी के खिलाफ एक बड़ी सफलता का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया, पंजाब कर विभाग ने मई 2026 के दौरान 85.4 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग रैकेट का सफलतापूर्वक पदार्फाश किया है और लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टर को बोगस लेन-देन के जरिए 15.56 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि सिपू की जांच में सामने आया कि टैक्स धोखाधड़ी के लिए गैर-मौजूद फर्मों, फर्जी इनवॉइस, फर्जी डेबिट नोट्स और जाली ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्डों का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के तहत संबंधित फर्म के डायरेक्टर को पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और इस धोखाधड़ी से जुड़े लाभार्थियों से लगभग 3 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।

अपने प्रेस बयान के अंत में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन्नत डेटा एनालिटिक्स, ई-वे बिल की बारीकी से जांच, फास्टैग वेरिफिकेशन और गुप्त जानकारियों का उपयोग करके सरकारी राजस्व की रक्षा करने और ईमानदार टैक्सदाताओं को समान माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री ने फर्जी बिलिंग और संगठित टैक्स चोरी के नेटवर्क के खिलाफ सरकार की सख्त जीरो-टॉलरेंस नीति को फिर दोहराया और संकल्प लिया कि आबकारी एवं कर विभाग सहायता, सख्त निगरानी और बिना किसी समझौते के इन्फोर्समेंट के संतुलित तरीके से असली टैक्सदाताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगा।

पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी : डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1241 लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।

इस सम्बन्धी ओर जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, मानसा, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर तथा मालेरकोटला के कुल 1241 पात्र लाभार्थियों के आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे।इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला अमृतसर के 546, बरनाला के 19, बठिंडा के 14, फरीदकोट के 10, श्री फतेहगढ़ साहिब के 21, जालंधर के 129, कपूरथला के 90 तथा मानसा के 27 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार पटियाला के 39, पठानकोट के 208, एस.ए.एस. नगर के 22, एस.बी.एस. नगर के 103 तथा मालेरकोटला के 13 लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा पात्र कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा सिद्ध हो रही है तथा बेटियों के विवाह के समय पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला हो तथा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने तथा राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

गैंगस्टरों ते वार का 132वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 446 स्थानों पर छापेमारी; 192 गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राज्य में चल रहे निर्णायक अभियान ह्यगैंगस्टरों ते वारह्ल के 132वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में पहचाने और मैप किए गए 446 स्थानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि ह्यगैंगस्टरों ते वारह्ल– पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए चलाया जा रहा एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाई कर रही हैं।

132वें दिन पुलिस टीमों ने 192 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ एक हथियार भी बरामद किया, जिससे अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियां 33,119 हो गई हैं।इसके अलावा 57 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 7 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 3 भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है।लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में सूचना दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ह्ययुद्ध नशों विरुद्धह्ल के 457वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए आज 75 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 673 ग्राम हेरोइन, 74 किलोग्राम भुक्की, 1900 नशीली गोलियां तथा 31,850 रुपये की ड्रग मनी बरामद की।इसके साथ ही केवल 457 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 66,093 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 2 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए सहमत भी कराया है।

चुन्नी लाल सचदेवा डीएवी पब्लिक स्कूल जैतो में डीएवी स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया

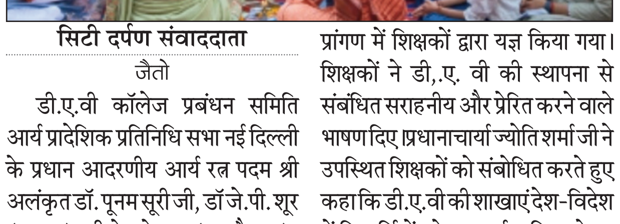

सिटी दर्पण संवाददाता
जैतो

डी.ए.वी कॉलेज प्रबंधन समिति आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान आदरणीय आर्य रत्न पदम श्री अलंकृत डॉ. पूनम सूरी जी, डॉ जे.पी. शूर (प्रधान), वी.के चोपड़ा (डायरैक्टर), मंत्री डॉ. नीलम कामरा (क्षेत्रीय निदेशिका), अजय गोस्वामी जी (अध्यक्ष), डॉ सतवंत कौर भुल्लर (मैनेजर), समीता शर्मा (क्षेत्रीय सहायक) इनके मार्ग दर्शन और दिशा निर्देश से चुन्नीलाल सचदेवा डी.ए. वी. सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जैतो में प्रधानाचार्या ज्योति शर्मा जी के नेतृत्व में डी.ए. वी स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर स्कूल के प्रांगण में शिक्षकों द्वारा यज्ञ किया गया। शिक्षकों ने डी,.ए. वी की स्थापना से संबंधित सराहनीय और प्रेरित करने वाले भाषण दिए।प्रधानाचार्या ज्योति शर्मा जी ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि डी.ए.वी की शाखाएं देश-विदेश में विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक शिक्षा देकर उनके भविष्य को बेहतरीन तरीके से उज्ज्वल करने में अपना भरपूर योगदान दे रहीं हैं। इसी दौरान उन्होंने डी.ए.वी. संस्थान की गौरवशाली परंपरा तथा शिक्षा के क्षेत्र में उसके महत्त्वपूर्ण योगदान के बारे में भी बताया। प्रधानाचार्या जी ने अपनी और डी.ए.वी मैनेजमेंट की तरफ से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समूह स्टाफ को डी.ए. वी स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी।

पीएयू में चन्नी का किया स्वागत; विशेष ग्रांट के लिए सौंपा मांग पत्र

सिटी दर्पण संवाददाता
लुधियाना

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य में फिर से सत्ता में वापसी करेगी।वड़िंग, जो लुधियाना से सांसद भी हैं, आज यहां अपने सहयोगी एवं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिले, जो कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन भी हैं और पीएयू के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे।

इस अवसर पर वड़िंग ने स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएयू परिसर में चन्नी का स्वागत किया।उन्होंने कहा कि चन्नी न केवल स्थायी समिति के चेयरमैन हैं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि वह स्वयं, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य सभी नेता एकजुट हैं तथा 2027 में पंजाब में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चन्नी को एक विस्तृत

ज्ञापन सौंपते हुए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के लिए अनुसंधान कार्यों हेतु एकमुश्त 1000 करोड़ रुपये की विशेष ग्रांट तथा इसके अलावा, प्रतिवर्ष 50 से 60 करोड़ रुपये की नियमित सहायता राशि देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीएयू को लंबे समय से आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है और कई बार कर्मचारियों तथा वैज्ञानिकों को वेतन देने के लिए भी धन की कमी हो जाती है।उन्होंने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीएयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि हरित क्रांति की शुरूआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी।

जबकि नगर कौंसिल चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत संबंधी दावों पर पूछे गए सवाल के जवाब में, वड़िंग ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी ये चुनाव जीतती रही है, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव हार जाती है। उन्होंने कहा कि वास्तव में पिछली सरकारों की तुलना में आप का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। आप सरकार के दौरान विपक्ष का प्रदर्शन पहले की तुलना में कहीं बेहतर रहा है।एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था, नशे, रोजगार और वित्तीय प्रबंधन के मामलों में आप सरकार पूरी तरह विफल रही है और राज्य को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्याएं अब आम बात बन गई हैं।हालात इतने खराब हैं कि आप सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और हर पंजाबी इसका खामियाजा भुगत रहा है।इसी तरह, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की पुलिस के साथ हुई झड़प और बाद में मांगी गई माफी के बारे में पूछे जाने पर वड़िंग ने उन्हें मंदबुद्धि करार दिया।उन्होंने कहा कि पुलिस से उलझने के बजाय बिट्टू को पंजाब के लोगों को बताना चाहिए कि दो साल मंत्री रहने के दौरान उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्होंने युवाओं को कोई रोजगार दिया है या पंजाब में कोई नई रेल लाइन बिछाई है?

दिल में छेद की बीमारी से वर्षों तक जूझती रहीं गुरप्रीत कौर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने दिया नया जीवन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब के लोगों को उपचार के खर्च की चिंता से मुक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रही है।इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है।

इस योजना को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है और अब तक इसमें 45 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है।विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थितियों में हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है और अनेक लाभार्थियों ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।ऐसी ही एक लाभार्थी हैं बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर, जिनका जीवन हृदय की एक गंभीर बीमारी के कारण अचानक संकट में आ गया था। जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में एक बड़ा छेद है, तो उन्हें न केवल स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा, बल्कि उपचार के भारी खर्च की चिंता भी सताने लगी। लेकिन एम्स बठिंडा में सफल उपचार और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के सहयोग से उन्हें जीवन का नया अवसर मिला।

अधिकांश लोगों के लिए हृदय की धड़कन ऐसी चीज है जिसके बारे में वे कभी सोचते भी नहीं।यह जीवन के हर सुख-दुख के साथ चुपचाप चलती रहती है।लेकिन गुरप्रीत कौर की हर धड़कन अनजाने में एक छिपे हुए खतरे को अपने साथ लिए हुए थी। अब तक गुरप्रीत का जीवन अपने परिवार की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द सामान्य रूप से चल रहा था।किसी को अंदाजा नहीं था कि वह जन्म से ही हृदय की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थीं, जो वर्षों तक सामने नहीं आई।

जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनके हृदय के ऊपरी दोनों कक्षों के बीच 22 मिलीमीटर का बड़ा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (ए एस डी) था।इसके कारण रक्त प्रवाह में असंतुलन पैदा हो गया था और हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था।यदि इसका उपचार नहीं किया जाता, तो आगे चलकर यह हृदय विफलता जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता था।बीमारी का पता चलते ही परिवार में चिंता का माहौल बन गया। एक ओर स्वास्थ्य की चिंता थी, दूसरी ओर उपचार का खर्च भी एक बड़ी चुनौती था।

गुरप्रीत कौर बताती हैं, सबसे पहले मेरे मन में इलाज के खर्च का ही विचार आया।मुझे चिंता थी कि हम इतना खर्च कैसे उठा पाएंगे।ऐसा लग रहा था जैसे हमारा परिवार जीवन के एक बहुत कठिन मोड़ पर खड़ा हो।

एम्स बठिंडा के विशेषज्ञों ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की सलाह दी। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 मई 2026 को कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में सामान्य एनेस्थीसिया के तहत यह प्रक्रिया की गई। इस दौरान 24 मिलीमीटर का एम्प्लाट्जर सेप्टल ऑक्लूडर डिवाइस लगाकर हृदय के छेद को बंद किया गया।

परिवार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पर भरोसा किया, जिसके तहत लगभग एक लाख रुपये की उपचार लागत कवर की गई।यह प्रक्रिया जोखिमपूर्ण थी और सहमति दस्तावेजों में संभावित हृदय संबंधी जटिलताओं, हीमोडायनामिक अस्थिरता तथा गंभीर चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता जैसी आशंकाओं का उल्लेख किया गया था।

कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब के बाहर परिवार के सदस्य हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गुरप्रीत के पति उस समय को याद करते हुए कहते हैं, हम केवल प्रार्थना ही कर सकते थे।हर मिनट बहुत लंबा लग रहा था। जब डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि सब कुछ सफल रहा, तो ऐसा लगा जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।

यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और कोई जटिलता सामने नहीं आई।गुरप्रीत के लिए यह एक स्वस्थ भविष्य की ओर नई शुरूआत थी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत मिला आर्थिक सहयोग परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसने उन्हें ऐसे भारी खर्च से बचा लिया जो उनके लिए असहनीय हो सकता था।पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता के वास्तविक उद्देश्य को दशार्ता है। उन्होंने कहा, किसी भी परिवार को आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुणवत्तापूर्ण उपचार से वंचित नहीं रहना चाहिए।गुरप्रीत की स्वस्थता इस बात का प्रमाण है कि समय पर चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सुरक्षा न केवल जीवन बचा सकती है, बल्कि परिवारों की गरिमा भी बनाए रख सकती है।आज गुरप्रीत कौर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के हजारों अन्य लाभार्थियों की तरह, नई उम्मीद और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन की ओर आगे बढ़ रही हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 1,75,210 मरीजों को लाभ मिल चुका है और 3,43,370 उपचार किए जा चुके हैं।योजना पर अब तक 581.90 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो राज्य में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

संक्षिप्त-समाचार

जेल में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना के लिए संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी तय होगी: डॉ. रवजोत सिंह

चंडीगढ़। भविष्य में किसी भी जेल में हिंसक घटना, सुरक्षा में कोताही या प्रशासनिक लापरवाही सामने आने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज यहां पंजाब भवन में पंजाब की सभी जेलों के सुपरिंटेंडेंटों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार जेलों में सुरक्षित, अनुशासित और सुधारात्मक माहौल सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जेलों में हिंसक घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान जेल प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्थाओं, कैदियों की भलाई और विभागीय कार्यक्षमता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. रवजोत सिंह ने जेल अधिकारियों को अपनी कार्यक्षमता का लगातार मूल्यांकन करने, कमजोरियों की पहचान करके उन्हें दूर करने और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक सक्षम और जिम्मेदार अधिकारी वह होता है जो उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पेशेवर तरीके से निभाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेलों के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा, अनुशासनहीनता या गैर-कानूनी गतिविधि को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल प्रबंधन को और मजबूत, आधुनिक और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए जेल मंत्री ने कहा कि जेलों का मुख्य उद्देश्य केवल कैदियों को हिरासत में रखना नहीं है, बल्कि उनके सुधार, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा से पुनः जोड़ने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाना है। उन्होंने जेल प्रशासन को कैदियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोवैज्ञानिक सहायता जैसे उपायों पर विशेष ध्यान देने के आदेश भी दिए। बैठक के दौरान जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग की विभिन्न गतिविधियों और सुधारात्मक कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसमें कैदियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन प्रबंधन, स्टाफ की भर्ती, बुनियादी ढांचे का विकास और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर जेल विभाग के सचिव मोहम्मद तईब, ए.डी.जी.पी. जेल आर.के. जायसवाल के अलावा पंजाब की सभी जेलों के सुपरिंटेंडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब के राज्यपाल ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र उठाया

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा, जिसको 1 मई 2026 को हुई अपनी बैठक के समाप्त होने के उपरांत सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब राज्यपाल के 31 मई 2026 के आदेशानुसार इस सत्र को औपचारिक रूप से उठा दिया गया है।

एस.सी. कमीशन द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को 4 जून को तलब

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जातिसूचक शब्द प्रयोग करने के मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 4 जून 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ध्यान में आया था कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अपने धूरी दौरे के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस बाबत एस.एस.पी. संगरूर से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आज पेश की गई रिपोर्ट पर आयोग ने असहमति जताई है।

गैस रिसाव होने से 3 मजदूरों की मौत पर वड़िंग ने गहरा दुख व्यक्त किया

लुधियाना। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गैस रिसाव के चलते तीन मजदूरों की मौत और कुछ अन्य लोगों के बीमार होने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार मृतकों के परिवारों को तुरंत और उचित मुआवजा प्रदान करे। यहां जारी एक बयान में, वड़िंग ने कहा कि लुधियाना में हुई दुखद गैस रिसाव की घटना के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है, जिसमें तीन मजदूरों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दर्दनाक है, जिसके कारण प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों और समाज को गहरा दुःख, नुकसान और पीड़ा झेलनी पड़ी है। इस अवसर पर वड़िंग ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, प्रार्थना की है कि परमात्मा उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की बल और साहस प्रदान करे। उन्होंने उपचाराधीन लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना की है।

साल में एक लंबी छुट्टी के बजाए कई छोटी यात्राएं पसंद कर रही है जेन जेड पीढ़ी: एयरबीएनबी रिपोर्ट

चंडीगढ़। भारत की जेन जेड पीढ़ी यात्रा के पारंपरिक तौर-तरीकों को बदल रही है। साल में एक लंबी छुट्टी के बजाय, अब यह पीढ़ी अपनी पसंद और अचानक बनने वाले प्लान के अनुसार यात्राओं को तरजीह दे रही है। एयरबीएनबी की नई रिपोर्ट नेवर द सेमः द न्यू रूल्स ऑफ जेन जेड ट्रेवल इन इंडिया के अनुसार, जेन जेड के लिए यात्रा केवल घूमने-फिरने का साधन नहीं, बल्कि अपनी पहचान और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन चुकी है। एयरबीएनबी के भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के कंट्री हेड अमनप्रीत बजाज ने कहा, जेन जेड के लिए यात्रा जितनी नई जगहों और अनुभवों को खोजने का माध्यम है, उतनी ही खुद को अभिव्यक्त करने का भी जरिया है। यही बात उन्हें सबसे अधिक सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से यात्रा करने वाला यात्री वर्ग बनाती है। इस पीढ़ी की खासियत यह नहीं है कि वे कितनी बार यात्रा करते हैं, बल्कि यह है कि वे यात्रा क्यों करते हैं ताकि वे खुद को और बेहतर ढंग से महसूस कर सकें। एयरबीएनबी पर हम देख रहे हैं कि इस पीढ़ी के लिए यात्रा उनके जीवन के सबसे व्यक्तिगत फैसलों में से एक बन गई है। वे कहां जाते हैं, किसके साथ जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कहां ठहरते हैं, इन सभी विकल्पों के जरिए वे अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। एयरबीएनबी इसी बदलती सोच और यात्रा शैली के अनुरूप बना है। यह बदलाव भारत को नए नजरिए से देखने, समझने और खोजने के अवसरों का एक नया अध्याय खोल रहा है।

यजत शिंगल (एआईआर 21) ने श्री चैतन्य से हरियाणा एवं ट्राइसिटी टॉपर बनकर किया शानदार प्रदर्शन

चंडीगढ़। श्री चैतन्य के छात्रों ने जेईई एडवांस्ड 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार परिणाम हासिल किए। संस्थान के 3 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 50 में, 4 छात्रों ने टॉप 100 में और 17 छात्रों ने टॉप 1000 रैंकों में स्थान प्राप्त किया। विशेष रूप से, श्री चैतन्य नॉर्थ रीजन का एकमात्र संस्थान बनकर उभरा जिसने टॉप 50 में 3 छात्रों को स्थान दिलाया, जिससे शीर्ष इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों को तैयार करने की उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। इस सफलता की कहानी का नेतृत्व यजत शिंगल ने किया, जिन्होंने एआईआर 21 प्राप्त कर हरियाणा और ट्राइसिटी टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। श्री चैतन्य के दो वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र और भवन विद्यालय, पंचकूला के विद्यार्थी यजत को बचपन से ही गणित के प्रति विशेष रुचि रही है। उनकी उपलब्धियों में आईएनएमओ में चयन, प्रतिष्ठित आईएमओटीसी कैंप में भागीदारी, आईएनसीएचओ 2026 में उपस्थिति तथा जेईई मेन 2026 में एआईआर 100 शामिल हैं। डीपीएस बठिंडा से कक्षा 10 तक की पढ़ाई पूरी करने वाले यजत प्रतिदिन लगभग आठ घंटे स्व-अध्ययन करते थे और अवधारणात्मक समझ पर विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने कहा कि यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो स्वयं को पूरी तरह उसके लिए समर्पित कर दीजिए। उनकी माता, जो एक आइलेट्स ट्रेनर प्रशिक्षक हैं, ने कहा कि रैंक से भी अधिक हमें उनकी ईमानदारी, अनुशासन और सीखने के प्रति प्रेम पर गर्व है। छात्रों को बधाई देते हुए, श्री चैतन्य नॉर्थ के अकादमिक निदेशक मृणाल ने कहा किये उपलब्धियाँ वर्षों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता का परिणाम हैं। हमारे छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से असाधारण लक्ष्य हासिल किए जा सकते है।

लेबनान में लड़ाई तेज, हिजबुल्लाह ने इजराइली सेना पर रॉकेट दागे, आईडीएफ का ब्यूफोर्ट पर कब्जा

आईडीएफ ने किए 36 से ज्यादा हमले, 12 लोग मारे गए और 35 अन्य घायल हो गए

एजेंसी (हि.स.)
बेरूत (लेबनान)

लेबनान में इस समय ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने रविवार को पूरे दिन हिजबुल्लाह के प्रमुख गढ़ों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके जवाब के लिए हिजबुल्लाह ने रात का समय चुना। आधीरात गुजर जाने के बाद अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक जून को करीब एक बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) पर रॉकेट और तोप के गोले दागे। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लिए अपराजेय माने जाने वाले ब्यूफोर्ट पर कब्जा कर उसे तगड़ी चुनौती दी है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में रविवार को आईडीएफ ने 36 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए और 35 अन्य घायल हो गए। टायर जिले के अल-अब्बासियेह शहर पर हमले में चार लोगों की जान चली गई। डेर अल-जहरानी के हाय अल अरब इलाके पर हमलों में आठ लोग मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए। अनेक रिहायशी घर तबाह हो गए। जदीदत अंसार इलाके पर हमले में दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हो गए। ओडाइसेह में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर कर किए गए हमले में तीन लोग घायल हो गए। टायर में हिराम अस्पताल के पास हमले में 13 मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के सदस्य घायल हो गए।

> इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में और आगे बढ़ने का आदेश दिया

फोटोः हि.स.

रिपोर्ट के अनुसार इजराइली सैनिकों ने लेबनान में एक रणनीतिक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है। इसके शिखर पर क्रूसेडरों का किला ब्यूफोर्ट है। ब्यूफोर्ट को यूनेस्को संरक्षित और विरासत स्थल घोषित कर चुका है। इस पर इजराइल का 2000 में पीछे हटने से पहले 18 वर्ष तक कब्जा रहा है।

हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना पर हमलों का दावा किया है। आतंकवादी समूह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सोमवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 1 बजे (रविवार को 22:00 जीएमटी) दक्षिणी लेबनान के योहमोर अल-शकीफ शहर के पूर्वी बाहरी इलाकों में इजराइली सेना पर बड़ी संख्या में रॉकेट और तोप के गोले दागे। समूह ने कहा कि यह हमला इजरायल के संघर्ष विराम के उल्लंघन और गांवों पर हमलों के जवाब में किया गया। इस बीच बताया गया है कि अब इजराइली सेना लिटानी नदी के भी आगे तक पहुंच गई है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में और आगे बढ़ने का आदेश दिया है। फ्रांस ने इस घटनाचक्र पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। बताया गया है कि इजराइली सेना ने दक्षिणी सीरिया के कुनेत्रा और डेरा प्रांतों के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया। वहां अस्थायी चौकियां बनाईं। आम नागरिकों और वाहनों की तलाशी ली और फिर वहां से वापस लौट गई।

मप्र पुलिस ने ड्रग्स तस्कर गिरोह का किया पदार्फाश, 20 करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर जब्त

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल

मध्य प्रदेश के मंदसौर पुलिस ने रविवार को सुनियोजित कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पदार्फाश कर 20 किलोग्राम अवैध ब्राउन शुगर (स्मैक) जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये है। पुलिस ने इस मामले में 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। यह कार्रवाई मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा की गई। टीम ने 02 चार पहिया वाहन, 7 मोबाइल फोन एवं 7 हजार 700 रुपये नगद भी जब्त किए हैं।

एसपी विनोद कुमार मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रविवार को थाना नई आबादी पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ तस्कर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप लेकर गुजरने वाले हैं। सूचना प्राप्त होते ही विशेष टीम का गठन कर रणनीतिक रूप से घेराबंदी की गई। संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 20 किलोग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान तस्करी एवं पायलटिंग में प्रयुक्त एक सुजुकी एस-क्रॉस तथा एक हुंडई क्रेटा कार, 07 मोबाइल फोन एवं 7 हजार 700 रुपये नगद भी जब्त किये गए। मोबाइल फोनों का तकनीकी एवं साइबर विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे गिरोह के नेटवर्क, सप्लायरों तथा वित्तीय लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जा सके। एसपी मीना ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। पुलिस द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों, सप्लाई चेन तथा अवैध आर्थिक नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। फरार आरोपी की तलाश के लिए भी पुलिस टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने हेमंत (50) पुत्र पूनम चंद्र वर्मा निवासी सृष्टि परिसर भानगढ़ का रोड इंदौर, मोना (48) पत्नी स्वर्गीय रमेश सेन निवासी नंदा नगर पाटनीपुरा इंदौर, राहुल (36) पुत्र लक्ष्मण लाल मीणा निवासी माली खेड़ा प्रतापगढ़ राजस्थान, सुभाष उर्फ पिंटू (46) पुत्र भंवरलाल नाहर जाति गुर्जर निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान और जितेंद्र उर्फ कारू (35) पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी माली का खेड़ा प्रतापगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अजीज उर्फ एजाज निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान अभी फरार है। एपी ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पूरी प्रतिबद्धता एवं दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है।

फोटोः हि.स.

ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे पर सरकारी प्रवक्ता की सफाई, कहा-अफवाह

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान (ईरान)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। मसूद ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वैश्विक मीडिया में रविवार को प्रसारित उनके इस्तीफा देने की खबर पर ईरानी प्रशासन ने देररात प्रतिक्रिया दी। प्रशासन की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने कहा कि यह महज अफवाह है।

इरना न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी शासन की प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी ने रविवार देर रात अपने एक्स हैंडल पर कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन मुश्किल दिनों में ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। उनका प्रशासन देश की समस्याओं को हल करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मोहजेरानी ने कहा कि वह अपने पद पर बने हुए हैं। उनके पद छोड़ने की खबर अफवाह है। उल्लेखनीय है कि मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने थोपे गए युद्ध के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए सभी एजेंसियों की सराहना की। राष्ट्रपति नेलोगों से मौजूदा वास्तविकता के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि देश की कुछ आर्थिक समस्याएं लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव के कारण पैदा हुई हैं। इसके कुछ देरबाद उनके इस्तीफे की खबर आई। यह तक कहा गया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र देश के सर्वोच्च नेता को सौंप दिया। सरकार ने कहा कि इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है।

फोटोः हि.स.

गंगाजल लेकर नोएडा लौट रहे कांवड़िए को मारी गोली

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगाजल लेकर नोएडा लौट रहे एक कांवड़िए को अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। घटना कनखल थाना क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घायल युवक की पहचान ग्रेटर नोएडा निवासी अजय के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल नोएडा लौट रहा था। कांवड़ियों का यह दल गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के समर्थन में 221 लीटर गंगाजल की विशेष कांवड़ लेकर यात्रा कर रहा था। दल में करीब दस गौसेवक शामिल बताए गए हैं। बताया गया कि रविवार देर रात यात्रा के दौरान थकान और अंधेरा होने के कारण कांवड़ियों का दल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निकट हाईवे किनारे विश्राम के लिए रुक गया। इसी दौरान हाईवे के ऊपर बने पुल पर कुछ युवक शराब पीते हुए शोर-शराबा और गाली-गलौज कर रहे थे। कांवड़ियों की ओर से विरोध किए जाने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि कुछ देर बाद वे युवक पुल से नीचे उतरकर कांवड़ियों के पास पहुंचे और उनमें से एक ने अजय के कंधे के पास गोली चला दी।

जेईई एडवांस्ड-2026 की परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल, कट-ऑफ में 18 अंक की बढ़ोतरी

> टॉप थ्री पर दिल्ली जोन के शुभम, कबीर और जतिन

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष परीक्षा में दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर रहे, जिन्होंने 329 अंक प्राप्त किए, जबकि जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह शीर्ष तीनों स्थानों पर दिल्ली जोन के अभ्यर्थियों का कब्जा रहा।

आईआईटी रुड़की ने परिणाम निर्धारित समय से पहले जारी करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी भी प्रकाशित कर दी। अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से देख सकते हैं। इस वर्ष जेईई एडवांस्ड के लिए 1,87,389 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 1,79,694 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 56,880 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। सफल अभ्यर्थी अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया (जोसा) की काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे। सफल अभ्यर्थियों में 10,107 छात्राएं भी शामिल हैं। इस बार सामान्य वर्ग की कट-ऑफ 92 अंक रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 अंक अधिक है। विषयवार कट-ऑफ 8 अंक निर्धारित की गई। लगभग 31.65 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। जोन के आधार पर भी कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईआईटी दिल्ली जोन से शुभम कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया। आईआईटी मद्रास जोन से मोहित शेखर शुक्ला चौथे स्थान पर रहे। आईआईटी मुंबई जोन के बी. जयकृष्ण श्रीनिवास ने छठा स्थान हासिल किया। आईआईटी रुड़की जोन के निकुंज अग्रवाल 11वें, आईआईटी कानपुर जोन के रिद्धेश अनंत बेंडाले 18वें तथा आईआईटी भुवनेश्वर जोन के भावेश पात्र 29वें स्थान पर रहे। आईआईटी गुवाहाटी जोन के यशराज सिंह ने 122वीं रैंक हासिल की।

महिला अभ्यर्थियों में आईआईटी दिल्ली जोन की आरोही देशपांडे सर्वश्रेष्ठ रहीं। उन्होंने 360 में से 280 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय रैंक सूची में 77वां स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि जेईई एडवांस्ड देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार है।

फोटोः हि.स.

बंगाल मंत्रिमंडल का विस्तार, 35 ने ली शपथ शुभेंदु सरकार के मंत्रियों की संख्या हुई 41

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल की पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार किया गया। लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

समारोह की शुरूआत वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान के साथ हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्वयं कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रविवार को उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा करते हुए 35 नए मंत्रियों के शपथ लेने की जानकारी दी थी। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने मंत्रियों के नामों की घोषणा की। पूर्ण मंत्री के रूप में तापस राय, मनोज उरांव, अर्जुन सिंह, गौरीशंकर घोष, दीपक बर्मन, अरूप कुमार दास, स्वपन दासगुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, शंकर घोष और दुधकुमार मंडल ने शपथ ली। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के रूप में मालती रावा राय, राजेश महतो और इंद्रनील खां को शामिल किया गया। वहीं राज्य मंत्री के रूप में अशोक डिंडा, कौशिक चौधरी, जुएल मुर्मू, हरेकृष्ण बेरा, शांतनु प्रमाणिक, उमेश राय, पूर्णिमा चक्रवर्ती, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, नदिया के चांद बाउड़ी, गर्गी दास घोष, अमिय किस्कू, कलिता माझी, विराज विश्वास, सुमना सरकार, आनंदमय बर्मन, विशाल लामा और दीपंकर जाना समेत अन्य नेताओं ने शपथ ग्रहण की।

फोटोः हि.स.

करियर दर्पण

बीपीसीएल में मिड-सीनियर स्तर के पदों पर भर्ती

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मिड-सीनियर स्तर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए विभिन्न विभागों में अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती संबंधी अधिसूचना 31 मई 2026 को जारी की गई। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक कंपनी के आधिकारिक करियर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल), कंपनी सेक्रेटरी, वित्त, पेट्रोकेमिकल्स तथा वे-साइड एमिनिटीज (डब्ल्यूएसए) विभागों में पद भरे जाएंगे। बीपीआरएल में 5, कंपनी सेक्रेटरी में 4, पेट्रोकेमिकल्स में 2 और डब्ल्यूएसए में 5 पद निर्धारित किए गए हैं। वित्त विभाग में रिक्तियां आवश्यकता के अनुसार भरी जाएंगी।

योग्यता और आयु सीमा

बीपीआरएल के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास बीई/बीटेक अथवा भूविज्ञान/भूभौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। कंपनी सेक्रेटरी पद के लिए आईसीएसआई की योग्यता अनिवार्य है, जबकि वित्त विभाग के लिए सीए या आईसीडब्ल्यूए पात्रता निर्धारित की गई है। पेट्रोकेमिकल्स और डब्ल्यूएसए पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग या प्रबंधन क्षेत्र में डिग्री आवश्यक होगी। अधिकांश पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 34 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। कुछ वरिष्ठ पदों पर यह सीमा 55 वर्ष तक हो सकती है।

आकर्षक वेतनमान

चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मेट्रो शहरों में अनुमानित वार्षिक सीटीसी इस प्रकार है– ई-2 ग्रेड के पदों पर वार्षिक अनुमानित सीटीसी 21.07 लाख रुपये, ई-3 पर 24.99 लाख रुपये, ई-4 पर 30.21 लाख रुपये, ई-5 पर 34.45 लाख रुपये, ई-6 पर 39.82 लाख रुपये, ई-7 पर 45.38 लाख रुपये तथा ई-8 ग्रेड के पदों पर 55.49 लाख रुपये तक का वार्षिक पैकेज मिल सकता है।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस तथा पूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों को 1,180 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसमें 1,000 रुपये शुल्क तथा 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना का अध्ययन कर पात्रता और अन्य शर्तों की पुष्टि कर लें।

यूपी टीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी 3 और 4 जून को होगी लिखित परीक्षा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी लिखित परीक्षा 3 और 4 जून को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार परीक्षा दो दिनों तक दो-दो पालियों में संपन्न होगी। 3 जून की पहली पाली में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू विषय की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में हिन्दी, गणित, कृषि और संगीत गायन विषय के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसी प्रकार 4 जून की पहली पाली में अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और संगीत वादन विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में संस्कृत, वाणिज्य और कला विषय की परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी करने से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी थी, जिससे वे अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना पहले से बना सकें। टीजीटी भर्ती 2022 के तहत कुल 3539 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में बनाए गए 614 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति तथा एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टीजीटी प्रवेश पत्र लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पंजीकरण संख्या अथवा आवेदन संख्या, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

> **3539 शिक्षक पदों के लिए 8.68 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा**

DRDO DEAL में पेड इंटर्नशिप का बड़ा मौकाः बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेंगे 30 हजार रुपये, 30 जून तक करें आवेदन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तहत देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी ने साल 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 45 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें चयनित छात्रों को कुल 30,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले योग्य उम्मीदवार 30 जून 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 20 पद, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 20 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पद निर्धारित किए गए हैं।

इस इंटर्नशिप के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बेहद खास रखी गई हैं। इसमें देश के किसी भी एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक, बीई, एमटेक और एमएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। बीटेक और बीई के ऐसे छात्र जिन्होंने अपना तीसरा वर्ष या छठा सेमेस्टर पूरा कर लिया है, या जुलाई 2026 तक पूरा करने वाले हैं, वे फॉर्म भर सकते हैं। वहीं एमटेक और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले वर्ष या दूसरे सेमेस्टर के छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 10 अंकों के स्केल पर न्यूनतम 7.0 सीजीपीए होना अनिवार्य है, साथ ही डिग्री के पहले पांच सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैकलॉग या फेल का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाला 30,000 रुपये का स्टाइपेंड दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली 15,000 रुपये की किस्त तीन महीने की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद और दूसरी 15,000 रुपये की किस्त छह महीने पूरे होने पर मिलेगी, बशर्ते उम्मीदवार की महीने में कम से कम 15 दिन की उपस्थिति अनिवार्य हो। इस पूरी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि उनका चयन पूरी तरह से अकादमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरने के बाद अपने आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियों को साथ में संलग्न करना होगा। इसके बाद तैयार आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर भेजना होगा, जो हर हाल में 30 जून 2026 तक संबंधित कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। चयनित छात्रों को 15 जुलाई 2026 तक सूचित कर दिया जाएगा और इसकी ट्रेनिंग 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी।

केरल पीएससी में बंपर भर्तीः एलडीसी और ऑफिस अटेंडेंट सहित 59 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। केरल लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में लोअर डिवीजन टाइपिस्ट, ऑफिस अटेंडेंट, कंप्यूटर सहायक और असिस्टेंट सर्जन सहित कुल 59 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें न्यूनतम 10वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा जैसे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और टइयर प्राप्त उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी केरल ढरउ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 तय की गई है।

आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलेगा। उदाहरण के लिए, कार्यालय परिचारक के लिए वेतनमान 23,000 से 50,200 प्रतिमाह है, वहीं सहायक सर्जन जैसे उच्च पदों के लिए यह 63,700 से 1,23,700 प्रतिमाह तक जाता है।

विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। कार्यालय परिचारक के लिए 10वीं पास, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 12वीं पास, और लोअर डिवीजन टाइपिस्ट व कंप्यूटर सहायक पदों के लिए 12वीं पास के साथ टाइपिंग या कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी तरह सुरक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन के साथ पूर्व सैनिक होना जरूरी है, जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी (केवल महिला) के लिए होम साइंस, सोशल वर्क, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन आवश्यक है। सहायक सर्जन या इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS डिग्री के साथ मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अन्य तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा, OMR परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के बाद एक मेरिट सूची (रैंक लिस्ट) तैयार की जाएगी, जो कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक वैध रहेगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले केरल लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'Ane Time Registration' के जरिए अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

इस साल मैंने खेल को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखा: वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल 2026 में चमका 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का सितारा, बने सीजन के 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर'

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) का पुरस्कार जीतने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि इस सीजन उन्होंने दबाव में बल्लेबाजी करना और मैच की परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को ढालना सीखा है।

रविवार देर रात आरसीबी और गुजरात के बीच खेले गए खिताबी मुकाबले के बाद आयोजित अवॉर्ड समारोह में पुरस्कार जीतने के बाद प्रसारकों से बातचीत में वैभव ने कहा, इस सीजन मैंने दबाव में बल्लेबाजी करना सीखा है। मैंने यह भी सीखा है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को कैसे बदला जाए। आप हर मैच में एक जैसी बल्लेबाजी नहीं कर सकते। आपको मैच की स्थिति को समझकर उसी के अनुसार खेलना होता है, खासकर प्लेऑफ जैसे बड़े मुकाबलों में।

वैभव सूर्यवंशी ने अकेले दम पर जीते 5 बड़े अवॉर्ड्स, बताया सफलता का मंत्र

महज 15 वर्षीय वैभव ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए। उन्होंने 48.50 की औसत और 237.31 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर-2 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक और एक शतक भी निकला।

फोटोः हि.स.

वैभव ने इस सीजन व्यक्तिगत पुरस्कारों पर भी अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप और एमवीपी ऑफ द सीजन जैसे सभी प्रमुख सम्मान अपने नाम किए।

सीजन के बाद अपनी आगे की योजनाओं पर बात करते हुए वैभव ने कहा कि वह अब अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देंगे।

उन्होंने कहा, मुझे अपनी फिटनेस पर फोकस करना होगा क्योंकि मैं लंबे समय तक क्रिकेट खेलना चाहता हूं और चोटों से दूर रहना चाहता हूं।

उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के टीम प्रबंधन और सीनियर खिलाड़ियों का आभार जताते हुए कहा, सभी ने मेरा बहुत समर्थन किया है। टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है क्योंकि वे सभी उच्च स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं। उनसे सीखने का मौका मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है।

विश्व कप 2027 की तैयारी में जुटा वेस्टइंडीज शिमरॉन हेटमायर की वनडे टीम में वापसी

एजेंसी (हि.स.)
एंटीगुआ

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (सीडब्ल्यूआई) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला के लिए रविवार को टीम की घोषणा कर दी है। स्टार बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर की एक बार फिर वनडे टीम में वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ चोट से उबरने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने के लिए तैयार हैं।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने स्पष्ट किया है कि हेटमायर को 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम में दोबारा शामिल किया गया है। हेटमायर ने आखिरी बार जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था। इसके बाद वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई तीन वनडे श्रृंखलाओं से बाहर रहे थे। हाल ही में हुए टी20 विश्व कप में हेटमायर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 248 रन बनाए थे। हालांकि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उन्होंने सात पारियों में सिर्फ 78 रन बनाए। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ की चोट से उबरकर टीम में लौटे हैं।

श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज वनडे टीम

शाई होप (कप्तान एवं विकेटकीपर), अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जस्टिन ग्रीव्स, शिमरॉन हेटमायर, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स और शमार स्प्रिंगर।

वह जुलाई 2025 के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं। उनके साथ तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और जेडन सील्स भी टीम में शामिल हैं, जिनके कार्यभार पर विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती की भी टीम में वापसी हुई है। वह पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे का हिस्सा नहीं थे।

न्यूजीलैंड दौरे वाली टीम से अलिक अथानाजे, जोहान लेन, खैरी पियरे और रोमारियो शेफर्ड को बाहर कर दिया गया है। वेस्टइंडीज इस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और 2027 विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने की दौड़ में बना हुआ है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा रैंकिंग में शीर्ष आठ टीमें सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। मुख्य कोच डैरेन सैमी ने कहा कि श्रीलंका एक अनुशासित और मजबूत वनडे टीम है। उनके अनुसार यह श्रृंखला वेस्टइंडीज के लिए अपनी क्रिकेट पहचान को और मजबूत करने का अवसर होगी। श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैच 3, 6 और 8 जून को जमैका में खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें तीन टी20 और दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भी आमने-सामने होंगी।

सर्राफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की फीकी पड़ी चमक

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को शुरूआती कारोबार के दौरान मामूली गिरावट का रुख नजर आ रहा है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,57,030 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,59,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना सोमवार को 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह, चांदी के भाव में आई मामूली कमजोरी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को 2,79,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,57,180 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की

आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,57,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,57,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,59,590 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,46,290 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,57,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,43,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

नॉर्वे शतरंज छठा दौर: भारतीय सितारों के लिए कठिन दिन

खिताबी मुकाबला हुआ और रोमांचक

एजेंसी (हि.स.)
ओस्लो (नॉर्वे)

नॉर्वे शतरंज 2026 के छठे दौर में रोमांच अपने चरम पर रहा। ओस्लो में रविवार को खेले गए सभी तीन मुकाबलों का नतीजा निकला, जिससे खिताब की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई। विश्व नंबर-1 मैग्नस कार्लसन ने टूर्नामेंट के शीर्ष खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। सफेद मोहरों से खेलते हुए कार्लसन ने रणनीतिक मुकाबले में धीरे-धीरे दबाव बनाया और अंतिम चरण में बढ़त को जीत में बदल दिया।

इस जीत के साथ कार्लसन अंक तालिका में शीर्ष खिलाड़ियों के करीब पहुंच गए, जबकि फिरोजा को टूर्नामेंट में अपनी पहली क्लासिकल हार झेलनी पड़ी। दूसरे मुकाबले में वेस्ली सो ने भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद को लंबे संघर्ष के बाद मात दी। वेस्ली सो ने जटिल परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला और एंडगेम में अपने अवसरों का पूरा फायदा उठाते हुए पूरे तीन अंक हासिल किए। इस जीत के साथ अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए।

फोटोः हि.स.

दिन का तीसरा निर्णायक परिणाम तब आया जब जर्मनी के विन्सेंट कीमर ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश को पराजित किया। कीमर ने पूरे मुकाबले में पहल बनाए रखी और मिले अवसरों का लाभ उठाकर विश्व चैंपियन के खिलाफ अहम जीत दर्ज की। छठे दौर के बाद वेस्ली सो नॉर्वे शतरंज 2026 की अंक तालिका में शीर्ष पर हैं, जबकि अलीरेजा फिरोजा उनके करीब बने हुए हैं। खिताब की दौड़ अभी पूरी तरह खुली हुई है। महिला वर्ग में भी मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। दिन के दौरान एक क्लासिकल मुकाबले का फैसला हुआ, जबकि दो मैच आमार्गेडन टाईब्रेकर तक पहुंचे। मौजूदा महिला विश्व चैंपियन जू वेनजुन ने भारत की दिव्या देशमुख को लंबे संघर्ष के बाद हराकर दिन की एकमात्र क्लासिकल जीत दर्ज की। जू ने धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत की और एंडगेम में बढ़त को जीत में बदल दिया।

बिबिसारा असाउबायेवा और भारत की कोनेरू हम्पी के बीच क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके बाद खेले गए आमार्गेडन मुकाबले में असाउबायेवा ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक हासिल किए और एक बार फिर एकल बढ़त हासिल कर ली।

वहीं अन्ना मुज़िचुक और झू जिनर का क्लासिकल मुकाबला भी ड्रॉ रहा। आमार्गेडन में झू जिनर ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक अपने नाम किए।

छठे दौर के बाद महिला वर्ग में बिबिसारा असाउबायेवा 9.5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। दिव्या देशमुख 8.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि जू वेनजुन और अन्ना मुज़िचुक 8-8 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

प्रीमियर लीग: लिवरपूल को बड़ा झटका, इब्राहिमा कोनाते ने क्लब छोड़ने का फैसला किया

एजेंसी (हि.स.)
लिवरपूल

लिवरपूल एफसी ने रविवार को पुष्टि की कि उसके स्टार सेंटर-बैक इब्राहिमा कोनाते इस गर्मी में अनुबंध समाप्त होने के बाद क्लब छोड़ देंगे। क्लब और खिलाड़ी के बीच नए अनुबंध को लेकर बातचीत सफल नहीं हो सकी, जिसके चलते कोनाते ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि पिछले महीने फ्रांस के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने भरोसा जताया था कि नए अनुबंध पर सहमति बन जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी।

कोनाते के जाने से लिवरपूल को बड़ा झटका लगा है। वह इस सत्र क्लब छोड़ने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इससे पहले मोहम्मद सलाह और एंडी रॉबर्टसन भी क्लब से अलग हो चुके हैं। 27 वर्षीय कोनाते ने वर्ष 2021 में लिवरपूल का दामन थामा था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्लब को प्रीमियर लीग, एफए कप और दो लीग

कप खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिवरपूल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इब्राहिमा कोनाते इस गर्मी में अनुबंध समाप्त होने के बाद क्लब छोड़ देंगे। क्लब ने उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। 2024-25 के खिताबी सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले कोनाते का 2025-26 सत्र अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा। उनकी फॉर्म में गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोनाते का नाम यूरोपीय चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि वह जल्द ही फ्रांसीसी क्लब के साथ जुड़ सकते हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में सफल रहे थे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजार में भी आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

टेक शेयरों में आई तेजी के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान पॉजिटिव माहौल बना रहा। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 363.37 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की मजबूती के साथ 51,032.34 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,580.06 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

फोटोः हि.स.

इसके अलावा नैस्डेक 0.20 प्रतिशत उछल कर 26,972.62 अंक के स्तर पर बंद हुआ। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,074.46 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.16 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 10,409.28 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,183.34 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। दूसरी ओर डीएएक्स इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 25,104.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। दूसरी ओर, तीन एशियाई बाजार के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से आज सेट कंपोजिट इंडेक्स में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है।

गिरावट के साथ कारोबार कर रहे एशियाई बाजार में गिफ्ट निफ्टी 76 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,614 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12 प्रतिशत टूट कर 4,063.72 अंक के स्तर पर आ गया है।

आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक 3 जून से, रेपो रेट यथावत रहने की संभावना

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 3 से पांच जून तक होगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा पांच जून को नीतिगत निर्णय की घोषणा करेंगे।

विशेषज्ञों के मुताबिक, आरबीआई मुंबई में आयोजित होने वाली की इस बैठक में पश्चिमी एशिया संकट और भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति की चिंताओं तथा रुपये पर दबाव के कारण रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर यथावत रख सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि एमपीसी से इस बार प्रमुख ब्याज दरों रेपो रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। बढ़ती ऊर्जा कीमतों, कमजोर होते रुपये और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की वजह से आरबीआई अपने मुद्रास्फीति के अनुमान बढ़ा सकता है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल की मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई ने पश्चिम एशिया संघर्ष के ऊर्जा आपूर्ति, महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव का आकलन के लिए 'देखो और इंतजार करो' का रुख अपनाते हुए रेपो रेट को 5.25 फीसदी अपरिवर्तित रखा था।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार पर दबाव ऊपरी स्तर से फिसले सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

घरेलू शेयर बाजार में आज शुरूआती कारोबार के दौरान दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरूआत मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में थोड़ी और तेजी आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बिकवाली शुरू हो जाने के कारण इन दोनों सूचकांकों की चाल कमजोर होने लगी। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी 0.02 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे।

शुरूआती एक घंटे का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से इंफोसिस, टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, कोल इंडिया और एशियन पेंट्स के शेयर 3.88 प्रतिशत से लेकर 1.89 प्रतिशत की मजबूती के

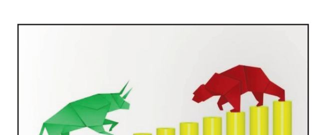

साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर 1.92 प्रतिशत से लेकर 1.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे।

अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,863 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 1,269 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,594 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 11 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 19 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान में और 32 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे।

बीएसई का सेंसेक्स आज 427.28 अंक की मजबूती के साथ 75,203.02 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरूआत होते ही खरीदारी के सपोर्ट से थोड़ी देर में ही यह सूचकांक उछल कर 75,367.93 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स की चाल में गिरावट आने लगी। लगातार हो रही बिकवाली के कारण सुबह 10 बजे के करीब यह सूचकांक गिर कर 74,784.72 अंक के स्तर तक आ गया। राहत की बात यही रही कि बिकवाली का दबाव बनने के बावजूद यह सूचकांक लगातार हरे निशान में ही कारोबार करता रहा।

जीएसटी राजस्व संग्रह मई में 3.2 फीसदी बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये के पार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 3.2 फीसदी बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले साल मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी महानिदेशालय ने सोमवार को आंकड़ों में बताया कि जीएसटी राजस्व संग्रह में यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात मिलने वाले कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई है।

आंकड़ों के अनुसार मई के दौरान घरेलू लेन-देन से केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई, जो घरेलू मांग को दशार्ती है।

फोटोः हि.स.

सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2 फीसदी रही है, जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है। इसी तरह आयात से आईजीएसटी संग्रह 19.1 फीसदी बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपये हो गया, जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है। इसके अलावा इस अवधि में जीएसटी 'रिफंड' 2.6 फीसदी बढ़कर 27,281 करोड़ रुपये हो गया। 'रिफंड' समायोजित करने के बाद मई में शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह 3.3 फीसदी बढ़कर लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले अप्रैल महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 8.7 फीसदी बढ़कर 2.43 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

घाटा | एमआर मनिवेनी की शेयर बाजार में निराशाजनक शुरूआत

अपर सर्किट के बावजूद घाटे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम करने वाली कंपनी एमआर मनिवेनी फूड्स के शेयरों ने सोमवार को स्टॉक मार्केट में जबरदस्त डिस्काउंट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 52 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 18.17 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 42.55 रुपये के स्तर पर हुई।

लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे थोड़ी देर में ही ये शेयर उछल कर 44.70 रुपये के अपर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। अपर सर्किट लगने के बावजूद पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशक प्रति शेयर 7.30 रुपये यानी 14.04 प्रतिशत के नुकसान में थे। एमआर मनिवेनी फूड्स का 27.04

फोटोः हि.स.

करोड़ रुपये का आईपीओ 22 से 26 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.74 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन सौ प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.88 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.09 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 52 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नया प्लांट तैयार करने और मशीनरी खरीदने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2.18 करोड़ रुपये हो गया। इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी शुद्ध लाभ उछल कर 4.13 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 3.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 119.61 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 155 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 203.52 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 116.19 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी के कर्ज में लगातार बढ़ोतरी होती रही।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मेरिट्रॉनिक्स का आईपीओ, 8 जून को लिस्टिंग संभव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड का 70.03 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में तीन जून तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद चार जून को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि पांच जून को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर आठ जून को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 141 रुपये से लेकर 149 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 1,000 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 2,000 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,98,000 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल

47 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 2.36 शेयर मार्केट मेकर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 49.91 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 30.02 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 15.05 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.02 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जून 2026 के दौरान प्रमुख सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करेगा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का क्षेत्र संचालन प्रभाग अपने चल रहे राष्ट्रव्यापी सांख्यिकीय डेटा संग्रह कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंडीगढ़ और पंचकुला के चयनित क्षेत्रों में जून 2026 के दौरान महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1950 से परिवारों और प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र कर रहा है और इसने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर एक मजबूत डेटाबेस विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से उत्पन्न जानकारी राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर योजना, नीति निर्माण और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करती है। डेटा संग्रह प्रशिक्षित एनएसओ अधिकारियों द्वारा ई-सिग्मा सॉफ्टवेयर और सुरक्षित वेब-आधारित प्लेटफॉर्म से लैस हैंड-हेल्ड डिजिटल उपकरणों (टैबलेट) का उपयोग करके किया जाता है। अधिकारी स्थापित वैज्ञानिक नमूनाकरण पद्धतियों के आधार पर चयनित परिवारों, उद्यमों, गांवों और शहरी ब्लॉकों का दौरा करते हैं।

पारिवारिक सर्वेक्षणों में परिवार के मुखिया या किसी भी जानकार सदस्य से जानकारी एकत्र की जाती है, जबकि उद्यम सर्वेक्षणों में अधिकृत प्रतिनिधि या मालिक जानकारी प्रदान करते हैं। एनएसओ ने दोहराया है कि सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है।

भाग लेने वाले परिवारों और उद्यमों की पहचान किसी भी रिपोर्ट या प्रकाशन में कभी भी उजागर नहीं की जाती है, और जानकारी का उपयोग विशेष रूप से सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

एनएसओ चंडीगढ़ और पंचकुला के चयनित स्थानों में निम्नलिखित सर्वेक्षण आयोजित करेगा

- राष्ट्रीय पारिवारिक आय सर्वेक्षण
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
- गैर-निगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय पारिवारिक यात्रा सर्वेक्षण
- घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सर्वेक्षण

चयनित सर्वेक्षण स्थानों में चंडीगढ़ में मनीमाजरा, मौली जागरा, दरिया, बुड़ैल, राजीव कॉलोनी, डड्डूमाजरा कॉलोनी, सेक्टर 8/9, 15/16, 20, 22/23, 29, 35/36, 42, 45, 46/47, 50 और 52 जैसे क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही पंचकुला में कालका, चंडी मंदिर, सेक्टर-5, सेक्टर-25, सेक्टर-27, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जैथल, बरवाला और मौली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, थोक मूल्य सूचकांक क्रेता मूल्य सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और कार्यात्मक सहकारी समितियों के त्वरित सर्वेक्षण (अप्रैल-सितंबर 2026) से संबंधित डेटा संग्रह के लिए समय-समय पर चयनित इकाइयों से संपर्क किया जा रहा है। भारत सरकार सभी चयनित परिवारों, उद्यमों, प्रतिष्ठानों और सहकारी संस्थानों से अपील करती है कि वे एनएसओ सर्वेक्षण अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और सटीक एवं पूर्ण जानकारी दें। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सूचित नीति निर्माण, प्रभावी शासन और राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जेएसजेबी 2.0 की प्रगति की समीक्षा की, जल संरक्षण परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश

पंचकूला को जल शक्ति अभियान 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बनाने का लक्ष्य

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज जिले में जल शक्ति अभियानझजल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की तथा सभी संबंधित विभागों को जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचकूला को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी जिला बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जेएसजेबी 2.0 का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देना, पारंपरिक जल निकायों का पुनर्जीवन तथा वनीकरण सहित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान कृषि एवं ग्रामीण विकास सहित जल से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी समन्वय को भी बढ़ावा देता है।

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने वन विभाग को चेक डैम (लघु बांध) निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अतिरिक्त वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके, जो सामान्यतः मानसून के दौरान बहकर व्यर्थ चला जाता है। उन्होंने कहा कि संचित जल का उपयोग सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सकता है। उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में तालाबों और जलाशयों का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), विकास एवं पंचायत विभाग तथा नगर निगम को स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी संस्थानों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण में जल निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने विकास एवं पंचायत विभाग तथा सिंचाई विभाग को पारंपरिक जल निकायों और टैंकों के जीर्णोद्धार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा जल के संग्रहण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोखता गड्ढों, स्थिरीकरण तालाबों तथा भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर भी बल दिया। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा अपनी प्रगति की जानकारी जेएसजेबी पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रदर्शन का आकलन पोर्टल पर अपलोड की गई पूर्ण हो चुकी रिचार्ज एवं जल भंडारण संरचनाओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

बैठक में मत्स्य विभाग के उपनिदेशक राजन खोड़ा, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक मेहरा, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक तथा लोक निर्माण, पंचायत, शिक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

30 साल बाद मिला तकनीकी कर्मचारियों को न्याय पीजीआई ने पूरी की 1120 पदोन्नतियों की प्रक्रिया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- 659 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ, लैब, एक्स-रे और रेडियोथेरेपी कैडरों का हुआ पुनर्गठन

पीजीआई ने तकनीकी कैडरों के पुनर्गठन और पदोन्नति से जुड़े तीन दशक पुराने मामले का समाधान कर एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने लैबोरेटरी, एक्स-रे और रेडियोथेरेपी तकनीकी कैडरों में पुनर्गठन लागू करते हुए करीब 1120 पदोन्नतियों की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे 659 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

संस्थान प्रशासन के अनुसार तकनीकी कैडरों के पुनर्गठन का मामला वर्ष 1992 से लंबित था। गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूट बॉडी की मंजूरी के बाद जुलाई 2025 में इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसके बाद निदेशक प्रो. विवेक लाल ने प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया, जिसने मार्च 1992 से दिसंबर 2024 तक के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की। विशेष सेल ने लगभग 659 कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करते हुए 193 डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) मेमोरेंडम तैयार किए। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में करीब 1120 पदोन्नतियों की प्रक्रिया पूरी की गई। लैबोरेटरी तकनीकी कैडर में सबसे व्यापक कार्य हुआ, जहां 520 कर्मचारियों से संबंधित 899 पदोन्नतियों को 104 डीपीसी मेमोरेंडम के माध्यम से मंजूरी दी गई। इनमें सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जैसे पद शामिल रहे। वहीं एक्स-रे कैडर में 111 कर्मचारियों से जुड़ी 173 पदोन्नतियां 64 डीपीसी मेमोरेंडम के माध्यम से और रेडियोथेरेपी कैडर में 28 कर्मचारियों की 48 पदोन्नतियां 25 डीपीसी मेमोरेंडम के जरिए स्वीकृत की गईं। प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठता सूची, सेवा रिकॉर्ड, भर्ती नियमों और पुराने पदोन्नति संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। कई रिकॉर्ड बिखरे हुए थे और उन्हें विभिन्न विभागों से जुटाकर दोबारा व्यवस्थित किया गया। प्रशासन ने इसे संस्थान की सबसे जटिल और व्यापक पदोन्नति प्रक्रियाओं में से एक बताया है। पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कहा कि तकनीकी कैडरों का पुनर्गठन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान, पहचान और पेशेवर विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने विशेष सेल और संबंधित विभागों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण के कारण वर्षों से लंबित यह मामला सफलतापूर्वक पूरा हो सका। इससे तकनीकी कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है।

फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण सुविधा दिलाने के लिए नगर निगम का विशेष अभियान शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- 30 जून तक पंचकूला में आयोजित होंगे पीएम स्वनिधि लोक कल्याण मेले
- मौके पर दस्तावेज जांच कर पात्र विक्रेताओं को मिलेगा ऋण लाभ

नगर निगम पंचकूला द्वारा 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान फुटपाथ विक्रेता एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के तहत उपलब्ध ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त श्रीमती सिमरनजीत कौर ने बताया कि इस एक माह तक चलने वाले अभियान के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा मौके पर ही फुटपाथ विक्रेताओं के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, ताकि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लोक कल्याण मेलों की जानकारी देते हुए श्रीमती सिमरनजीत कौर ने बताया कि 2 जून को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बीडीपीओ कार्यालय रायपुररानी में लाभार्थियों से दस्तावेज लिए जाएगें। 3 को बैंक आफ बडौदा द्वारा सामुदायिक केंद्र, सैक्टर-20, 4 को इंडियन बैंक द्वारा सामुदायिक केंद्र, गांव जलौली, 5 को यूनियन बैंक आर्फ इंडिया द्वारा बीडीपीओ कार्यालय रायपुररानी, 8 को यूको बैंक द्वारा गुगामाडी गांव रामगढ, 9 को केनरा बैंक द्वारा निगम कार्यालय सैक्टर-4 पंचकूला, 10 को बैंक आफ बडौदा द्वारा निचला गुरूद्वारा गांव माणक्या, 11 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बीडीपीओ कार्यालय रायपुररानी सहित अन्य स्थानों पर आयोजन होंगे।

संक्षिप्त-समाचार

यूटी चंडीगढ़ में पात्र किशोरियों हेतु एचपीवी टीकाकरण अभियान की अवधि बढ़ाई गई

चंडीगढ़। स्वास्थ्य विभाग, यूटी चंडीगढ़ ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशानुसार सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु पात्र किशोरियों के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस टीकाकरण अभियान की अवधि तीन माह (90 दिन) तक बढ़ाने की घोषणा की है। विस्तारित अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष की आयु प्राप्त न करने वाली सभी पात्र किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। इस विस्तार का उद्देश्य उन लाभार्थियों को अवसर प्रदान करना है, जो अभियान के प्रारंभिक चरण में टीकाकरण से वंचित रह गई थीं। एचपीवी वैक्सीन (गार्डासिल-4) यूटी चंडीगढ़ की सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सप्ताह के छह कार्य दिवसों पर उपलब्ध है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर एवं एचपीवी से संबंधित अन्य बीमारियों से बचाव का सुरक्षित एवं प्रभावी माध्यम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अनुशंसित आयु में टीकाकरण वायरस के संपर्क से पूर्व अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक नेताओं एवं आमजन से अभियान को सफल बनाने तथा सभी पात्र किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग ने किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण तथा चंडीगढ़ को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रोहतास जांगड़ा ने संभाला कार्यभार

पंचकूला। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रोहताश जांगड़ा ने आज सेक्टर-4 स्थित बोर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। कार्यभार संभालने के उपरांत जांगड़ा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है, वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उनका प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचे, ताकि श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर और अधिक बेहतर हो सके। श्रम कल्याण बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन रोहताश जांगड़ा सिरसा जिले के एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं तथा लंबे समय से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। चेयरमैनका कार्यभार संभालने के अवसर पर मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जगदीश चोपड़ा, हरियाणा एचपीएससी बोर्ड सदस्य सुभाष गंगा, जिला अध्यक्ष यतेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष नितिशा, जिला महामंत्री अंबर कुमार, विष्णु शर्मा, शुभम सिंह, सुखविंदर सिंह बराड़, बाबूलाल सैनी, सतपाल मेहता, रवि सैनी, पूर्व महामंत्री बलवान जांगड़ा, मीरा दुसाद, कृष्ण जलंधरा, सीएम विंडो एमिनेंट प्रकाश वीर जलंधरा, कुलविंदर सिंह, पीयूष मेहता, दिलीप सिंह, फकीरचंद मलेठिया, डॉ. अमरजीत चांनी, सुखविंदर सिंह बग्गा, डॉ. विनोद कुमार जांगड़ा, कृष्ण कुमार जांगड़ा, पूर्ण चंद्र सेन, महावीर जांगड़ा, बलजीत जांगड़ा, प्रवीण जांगड़ा, हनुमान कुंडू, आतिश लाखलान, रोहतास पलथानिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हरियाणा में मई माह के दौरान पेट्रोल की बिक्री में 6% तथा डीजल की बिक्री में 7% की वृद्धि

चंडीगढ़। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) - इंडियनऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल - देश भर में परिचालन और लॉजिस्टिक्स समन्वय जारी रखे हुए हैं ताकि कई क्षेत्रों में ईंधन की मांग में अचानक और तीव्र वृद्धि के बावजूद पेट्रोल (एमएस), डीजल (एचएसडी) और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा राज्य में 2025 की तुलना में मई माह के दौरान पेट्रोल की बिक्री में 6% तथा डीजल की बिक्री में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। डीजल श्रेणी में कुछ जिलों में उल्लेखनीय रूप से अधिक वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से महेंद्रगढ़ जिले में डीजल बिक्री में 24% तथा चरखी दादरी जिले में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के दिनों में, ओएमसी ने कई राज्यों में मौसमी कृषि गतिविधियों और कटाई कार्यों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की उल्लेखनीय रूप से अधिक खपत देखी है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी अपने टर्मिनलों, डिपो, पाइपलाइनों, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों और खुदरा आउटलेट्स के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। आपूर्ति दल, परिवहन नेटवर्क, टर्मिनल संचालन और चुनिंदा खुदरा आउटलेट्स बाजारों में निर्बाध उत्पाद आवागमन और समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24७7 कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां निर्बाध ईंधन आपूर्ति के लिए राज्य प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां स्टॉक की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही हैं और बढ़ी हुई मांग को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए रसद और वितरण योजना पर घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर रही हैं।

उपायुक्त ने सुनी 20 अलग-अलग समस्याएं कुछ का किया मौके पर समाधान

पंचकूला। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आज बरवाला तहसील के 29 गांवों के निवासियों की बस के लिए शैड बनाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा रोडवेज के जीएम को मौके का मुआयना कर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आज जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। उपायुक्त ने समाधान शिविर में जिलावासियों की 20 समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर बिना विलंब किए समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने समाधान शिविर में लंबित और रिओपन शिकायतें के मामलें में संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को अगले समाधान शिविर तक समस्याओं का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तत करने के निर्देश दिए। श्री सतपाल शर्मा ने सेक्टर-12ए निवासी की सीवरेज के कूड़ा करकट उठवाने की मांग पर कार्रवाही करते हुए नगर निगम के संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर सफाई करवाने के निर्देश दिए।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बापू धाम कॉलोनी में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान : 100 डेज कैंपेन के अंतर्गत सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कॉलोनी, चंडीगढ़ में 5 मई से 29 मई 2026 तक विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं सामुदायिक केंद्रों पर आयुष्मान आरोग्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान क्षय रोग (टीबी) के मामलों की शीघ्र पहचान एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए कुल 1,108 डिजिटल चेस्ट एक्स-रे तथा 117 सीबीएनएएटी परीक्षण किए गए। पुष्टि किए गए मरीजों को तुरंत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार सेवाओं से जोड़ा गया।

इस पहल का उद्देश्य उच्च जोखिम एवं संवेदनशील आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना तथा यस ! वी कैन एंड टीबी : भारत के नेतृत्व में, जनभागीदारी से सशक्त थीम के अंतर्गत जनभागीदारी को सशक्त बनाना था।

शिविरों के दौरान नागरिकों को टीबी के लक्षण, संक्रमण के तरीके, बचाव उपायों तथा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क जांच एवं उपचार सेवाओं के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। साथ ही टीबी से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने और समय पर उपचार हेतु लोगों को प्रेरित करने पर विशेष बल दिया गया।

क्षेत्र के पार्षद ने भी अभियान में सक्रिय सहभागिता करते हुए स्थानीय निवासियों से सामूहिक प्रयासों द्वारा क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाने की अपील की। यह अभियान चंडीगढ़ प्रशासन की टीबी उन्मूलन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता, समय पर स्क्रीनिंग, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता तथा जनभागीदारी आधारित स्वास्थ्य जागरूकता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हर वर्ग की भागीदारी जरूरी : प्रोफेसर सतीश गंधर्व

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्थान के विद्यार्थियों ने तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों को दशार्ते हुए सामाजिक चेतना जगाई। इसके साथ ही, अगद तंत्र विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनीता यादव ने अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे मरीज व उनके परिजनों तथा संस्थान के कर्मचारियों को नशे का सेवन न करने और दूसरों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु जन जागरूकता अभियान चला जा रहा है।

डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। परिवार, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे, ताकि युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाया जा सके। प्रोफेसर प्रह्लाद रघु ने आह्वान किया कि कि नशे की समस्या को छिपाने के बजाय उसे छोड़ने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लें और नशामुक्त, स्वस्थ एवं सकारात्मक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि उपचार का उद्देश्य केवल नशा छुड़ाना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ कर उसे समाज की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ना है।

इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनूप एम, असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराग कुशल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. समित मसंद, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धवल मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रितेश, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आकांक्षा राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रमोहन, असिस्टेंट प्रोफेसर महेश एम तथा मैट्रन डॉ. राजेंद्र के साथ संस्थान के विद्यार्थी व कर्मी तथा उपचार के लिए पहुंचे मरीज व उनके परिजन मौजूद रहे।

तीर्थाटन

पात्र वृद्धजन श्रद्धालुओं को निःशुल्क कराए जाएंगे सोमनाथ मंदिर के दर्शन

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 8 जून को सोमनाथ के लिए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन होगी रवाना

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
- 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण : उपायुक्त सतपाल शर्मा

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी पहल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पात्र वृद्धजन श्रद्धालुओं को पवित्र तीर्थस्थल श्री सोमनाथ मंदिर, प्रभास पाटन, वेरावल (गुजरात) के दर्शन करवाए जाएंगे। यह पर्व सोमनाथ मंदिर की 1000 वर्ष की अखंड आस्था तथा पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए 8 जून को एक विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। पात्र श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवास, भोजन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का चयन ह्यपहले आओ, पहले पाओह्न के आधार पर किया जाएगा। इसलिए पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह किया गया है। इस यात्रा पर होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। योजना के तहत आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, योजना के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण करवाने वाले सभी लाभार्थी 6 जून तक लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अपनी जानकारी अवश्य उपलब्ध करवाएं, ताकि यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जा सकें।

उपायुक्त ने जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वे इस जनहितकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और पवित्र सोमनाथ धाम के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। इनमें वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा अन्य सरकारी पहचान पत्र), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होने संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी स्व-घोषणा पत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना तथा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है।